A Daily News Magazine
इंदौर
बुधवार, 03 जून, 2026

सुबह सवेरे

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 241, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

कर्नाटक में आसान सत्ता बदलाव से 2029 का रोडमैप तैयार!

ओंकारेश्वर पांडेय

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए एक ऐतिहासिक पल में, कर्नाटक का लंबा सियासी नाटक किसी विस्फोट में नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हस्तांतरण के साथ समाप्त हुआ। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 28 मई को औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा दे दिया, जिससे डी.के. शिवकुमार - वोक्कालिगा के दमदार नेता और पार्टी के 'अंतिम समाधानकर्ता' - के लिए रास्ता साफ हो गया। वह 3 जून को बेंगलुरु के ग्लास हाउस में नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।

लेकिन यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। राहुल गांधी द्वारा बारीकी से लिखा गया यह परिवर्तन पार्टी के संघीय ढांचे में एक स्पष्ट संदेश भेजता है: क्षेत्रीय द्वंद्वों, टूटे वादों और नेतृत्व की ठप्पता का युग खत्म हुआ। आंतरिक समझौतों का सम्मान होगा। समयसीमा लागू होगी। और जो लोग सामूहिक हित को नुकसान पहुँचाएंगे - जिनमें कांग्रेस के भीतर मौजूद 'भाजपा के मोल' शामिल हैं - उन्हें अंजाम भुगतना होगा। जिसे व्यापक रूप से 2029 के आम चुनाव के पूर्वाभ्यास के रूप में देखा जा रहा है, उसमें हाई कमान ने रेत में एक स्पष्ट रेखा खींच दी है।

कांग्रेस पार्टी का हालिया इतिहास उन हारों से भरा पड़ा है जो चुनावी पराजय से नहीं, बल्कि आत्मघाती आंतरिक कलह से हुई हैं। कर्नाटक भी लगभग उसी दुखद सूची में शामिल हो गया था, और नेतृत्व ने अपनी नई निर्दयता को सही ठहराने के लिए पिछली विफलताओं के भूतों को आमंत्रित किया है। राजस्थान में, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच पाँच साल के लंबे गृह युद्ध ने जनता का विश्वास खो दिया, जिससे भाजपा ने 115 सीटों पर कब्जा कर लिया जबकि कांग्रेस 2023 के विधानसभा चुनावों में महज 69 पर सिमट गई।

छत्तीसगढ़ में, तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके डिप्टी टी.एस. सिंह देव के बीच गहरी दरार ने सीधे पार्टी की चौंकाने वाली हार में योगदान दिया। पंजाब में, हाई कमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ विद्रोह करवाया, उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया और साथ ही नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया।

पंजाब में इस 'गृह युद्ध' ने मतदाताओं को निराश कर दिया और राज्य ऐतिहासिक रूप से आम आदमी पार्टी के हाथों में चला गया।

हरियाणा में, हुड्डा-सेलजा की कड़वी दरार 2024 के विधानसभा चुनावों में विनाशकारी साबित हुई। हुड्डा खेमे ने लगभग 70 टिकट हासिल किए, जबकि सेलजा खेमा मात्र नौ पर सिमट गया, और दलित नेता ने दो सप्ताह तक प्रचार से भी दूरी बनाए रखी। इस आंतरिक कलह ने सीधे उस सरकार को खो दिया जिसे पार्टी जीतने की उम्मीद कर रही थी।

असम में, 2021 के विधानसभा चुनावों में आंतरिक कलह और गठबंधन की कमजोर रणनीति को हार के प्रमुख कारणों के रूप में देखा गया, जहाँ कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन 126 सदस्यीय सदन में भाजपा के 75 के मुकाबले मात्र 50 सीटें ही हासिल कर सका। केरल में भी, जबकि 2026 में यूडीएफ ने वापसी की, कांग्रेस जिला और स्थानीय स्तरों पर गहरे गुटबाजी के तनाव से जूझ रही है।

पार्टी अनुशासन से कोई समझौता नहीं होगा। पार्टी अध्यक्ष और हाई कमान के प्रति निष्ठा गैर-संवेदनशील है। केंद्रीय अधिकार को चुनौती देने वालों को अब जगह नहीं मिलेगी, और क्षेत्रीय दिग्गजों द्वारा पार्टी को बंधक बनाने के दिन खत्म हुए। 'भाजपा के मोल' और जो व्यक्तिगत लाभ के लिए आंतरिक तोड़फोड़ करेंगे, उनकी पहचान की जाएगी, उन्हें किनारे लगाया जाएगा और बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

अतीत की अराजकता के बिल्कुल विपरीत, कर्नाटक का परिवर्तन संस्थागत वार्ता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। 2023 की निर्णायक जीत के बाद की गई 50:50 सत्ता-साझाकरण की समझौते का पूरी तरह से सम्मान किया गया है। सूत्रों के अनुसार, हाई कमान ने नए मंत्रिमंडल को 'राजनीतिक रूप से संतुलित' बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें दलितों, पिछड़ा वर्गों और अल्पसंख्यकों को बेहतर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, साथ ही 60 वर्ष से कम उम्र के युवा चेहरों को शामिल किया जाएगा।

24×7 मीडिया कवरेज के इस युग में, राहुल गांधी की टीम ने कोई मौका नहीं छोड़ा- सिद्धारमैया के अपने मंत्रिमंडल के साथ नाश्ते की बैठक से लेकर शिवकुमार द्वारा अपने पूर्ववर्ती के पैर छूकर आशीर्वाद लेने तक, हर कदम को अधिकतम प्रभाव के लिए कोरियोग्राफ किया गया।

नेतृत्व उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने जमीनी कार्य और निष्ठा के साथ इसे अर्जित किया है। डी.के. शिवकुमार, जिन्होंने 50 दिन तिहाड़ जेल में बिताए, जिन्होंने अहमद पटेल की राज्यसभा जीत के लिए गुजरात के विधायकों को सुरक्षित रखा, और जिन्होंने भाजपा को ध्वस्त करने वाला 'पे-सीएम' अभियान चलाया, आज इसलिए ऊपर उठाए जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसे अर्जित किया। जो लोग आंतरिक कलह करेंगे, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पार्टी से ऊपर रखेंगे, या छुपकर भाजपा के लिए काम करेंगे, उन्हें कोई जगह नहीं मिलेगी।

'पे-सीएम' अभियान सितंबर 2022 में कर्नाटक कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया एक अत्यधिक आक्रामक, वायरल राजनीतिक गुरिल्ला मार्केटिंग अभियान था। इसे मई 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले तत्कालीन सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की छवि को मौलिक रूप से नुकसान पहुँचाने वाली सबसे प्रभावी कथा-निर्माण रणनीतियों में से एक माना जाता है। यह अभियान डी.के. शिवकुमार और सिद्धारमैया के नेतृत्व में तैयार और संचालित किया गया था।

अगले साल कई राज्यों में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, और 2029 का हाई-स्टेक आम चुनाव अब पूरी तरह फोकस में है, कांग्रेस एक लंबे, अनुशासित अभियान के लिए खुद को तैयार कर रही है। कर्नाटक ब्लूप्रिंट को राष्ट्रीय टेम्पलेट के रूप में स्थापित किया जा रहा है। जहां आलोचक सिद्धारमैया के विशाल ओबीसी और अहिंदा समर्थन आधार को अलग करने के जोखिम की ओर इशारा करते हैं, वहीं हाई कमान आश्वस्त है कि एक संतुलित मंत्रिमंडल - जिसमें दो उपमुख्यमंत्री, जिसमें एक दलित नेता शामिल हो सकते हैं - इस प्रभाव को कम कर देगा।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सेना में शामिल होंगे आधुनिक ड्रोन

- वर्तमान में चल रहे युद्ध में बन रहे हैं 'गेम चेंजर'
- लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने कर दिए बड़े दावे

नई दिल्ली (एजेंसी)। महाराष्ट्र के नासिक स्थित कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में भारतीय सेना के लिए एक अहम समारोह आयोजित किया गया, जहां 59 अफसरों ने अपनी एविएशन ट्रेनिंग पूरी की। इनमें से 25 अधिकारियों को बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद प्रतिष्ठित फ्लाइंग विंग्स प्रदान किए गए। इस अवसर पर सेना प्रशिक्षण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने कहा कि यह समारोह भारतीय सेना की उस व्यापक तैयारी का प्रतीक है, जिसके तहत अफसरों को आधुनिक युद्धक्षेत्र की चुनौतियों के लिए तैयार किया जाता है।

लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने कहा कि कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में पायलटों को लगभग तीन महीने की अवधि में बेसिक, एडवांस्ड और कॉम्बैट-खास ट्रेनिंग दी जाती है। उन्होंने बताया कि पिछले 23 सालों में इस संस्थान ने 1,794 अधिकारियों को ट्रेनिंग दे कर तैयार किया है, जिनमें लगभग 20 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। इसके अलावा मित्र देशों के सैन्य अधिकारी भी निमंत्रित हैं।

एक्सरसाइज एविएशन शक्ति से दिखाई गई युद्धक क्षमता– लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने बताया कि 'एक्सरसाइज एविएशन शक्ति' का उद्देश्य सेना के पायलटों और विमानों की युद्धक क्षमताओं का प्रदर्शन करना है। इस अभ्यास के दौरान यह दिखाया जाता है कि संघर्ष की स्थिति में समन्वय जरूरी है।

आधुनिक युद्ध में ड्रोन बन रहे गेम चेंजर– ड्रोन तकनीक पर बोलते हुए लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा ने कहा कि बड़े आकार के आधुनिक ड्रोन सेना को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम हैं। इनमें लगे उन्नत इलेक्ट्रो–ऑप्टिकल सेंसर और निगरानी प्रणालियां लंबी दूरी तक गतिविधियों पर नजर रख सकती हैं।

सीएटीएस की बढ़ती क्षमता और आधुनिक प्रशिक्षण

सीएटीएस की स्थापना के समय यहां केवल 3 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित होते थे। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 18 अलग–अलग कोर्स तक पहुंच गई है। हर वर्ष लगभग 150 अधिकारियों को विभिन्न एविएशन और ऑपरेशनल कोर्स के तहत प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षण में हेलीकॉप्टर संचालन, सामरिक उड़ान, युद्धक्षेत्र समन्वय और आधुनिक हवाई अभियानों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। भारतीय सेना में आर्मी एविएशन को हाल के वर्षों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका मिली है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों, सीमावर्ती इलाकों और आपदा राहत अभियानों में प्रशिक्षित एविएशन अधिकारियों की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

विदेशियों के लिए भारत में रहने के बदले नियम

- अब 180 दिन पूरे होने से पहले रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे
- ऑनलाइन अपील का भी ऑप्शन, होम मिनिस्ट्री ऐक्टिव

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों के भारत में रहने के नियमों में बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी करके रजिस्ट्रेशन और अपील से जुड़े नियमों में बदलाव की जानकारी दी। नए नियमों के मुताबिक विदेशी नागरिक अब भारत में उसके रहने के 180 दिन पूरे होने से पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। साथ ही ऑनलाइन अपील का ऑप्शन भी कर सकेंगे। पहले भारत में 180 दिन पूरे होने के बाद विदेशी नागरिकों को 14 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होता था। सरकार ने कहा है कि तय समय में काम हो।

ऑनलाइन अपील का प्रावधान जोड़ा गया– पहली बार ऑनलाइन अपील की व्यवस्था जोड़ी गई है। किसी आदेश से प्रभावित व्यक्ति अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के आयुक्त के पास ऑनलाइन अपील कर सकेगा। आदेश मिलने के 30 दिन के भीतर अपील करनी होगी। आयुक्त को संबंधित पक्ष की सुनवाई के बाद फैसला देना होगा। 60 दिन के भीतर मामले का निपटारा करने की कोशिश करना होगा।

बच्चों की नागरिकता से जुड़े नियम भी बदले– अगर माता–पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है और बच्चे की भारतीय नागरिकता बनाए रखना चाहता है, तो बच्चे पर विदेशी नागरिकों के रजिस्ट्रेशन वाले नियम लागू नहीं होंगे। 30 दिन के भीतर जानकारी देनी होगी।

सुप्रभात

गर्मी की शांत दुपहरी है

बाहर इक्का-दुक्का आवाज़ें हैं
दो गृहणियों के आपस में बातें करने
के अस्फुट स्वर हैं
दूसरे लोक से आते हुए

अभी-अभी एक स्कूटर
गुज़र कर गया है
दूर रेडियो पर सुगम संगीत में गायिका
ऊबी-डूबी आवाज़ में गा रही है
सावन आया तुम नहीं आए

छत पर धीमी आवाज़ में घूमता पंखा है
दीवाल पर टिक-टिक करती घड़ी है

बेटा-बहू काम पर गए हैं
पत्नी दूसरे कमरे में दुखती कमर
सीधी कर रही है

काम कुछ शेष नहीं
नाम कुछ होना नहीं है

यही समय है चुपचाप चले जाने का।
- चंद्रशेखर साकल्ले

48.32 लाख लोगों को फ्री में रजिस्ट्री कराकर देगी सरकार

मोहन कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले: 8वीं तक के बच्चों को स्कूल ड्रेस सिलवाकर देंगे

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के चहुंमुखी विकास, जन-कल्याण और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए 21 हजार 485 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई। साथ ही प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण के लिए ऐतिहासिक एवं दूरगामी निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 के तहत स्टॉम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूरी तरह माफ करने का फैसला किया है, जिसका संपूर्ण 3800 करोड़ रूपये का वित्तीय भार राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। इसके साथ ही प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत 17 हजार 59 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई, जिससे नए चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण और एमबीबीएस तथा पीजी सीटों में बढ़ोतरी का मार्ग प्रशस्त होगा।

- **भोजशाला में सरस्वती लोक बनेगा, जल गंगा अभियान पर 6.5 हजार करोड़ खर्च**

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश के लाखों परिवारों को उनकी आबादी वाली जमीन के रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज देने और सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को तैयार सिलाई की हुई यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।

एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन और सैटेलाइट सर्वे के जरिए आबादी क्षेत्र में बसे लोगों की संपत्तियों का चिह्नांकन किया गया था। इसके बाद उन्हें स्वामित्व पत्र दिए गए थे। अब सरकार इन संपत्तियों की रजिस्ट्री कराकर पंजीकृत दस्तावेज भी उपलब्ध कराएगी। प्रदेश के 55 जिलों में 48.80 लाख निजी संपत्तियां और करीब 19 लाख सरकारी संपत्तियां चिह्नित की गई हैं। रजिस्ट्री की प्रक्रिया में लगने वाला पंचायत उपकर और पंजीयन शुल्क सरकार स्वयं वहन करेगी। इस पर करीब 3800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है।

पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को गणवेश

मंत्रि–परिषद ने शासकीय शालाओं में कक्षा पहली से 8 वीं तक के विद्यार्थियों को सत्र 2026–27 से निविदा प्रक्रिया के माध्यम से सिली–सिलाई गणवेश प्रदाय करने का निर्णय लिया है। निविदा प्रक्रिया के लिए मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम को अधिकृत किया गया है।

बरगी जलाशय दुर्घटना की जांच के लिए न्यायिक जाँच आयोग के गठन का अनुसमर्थन

मंत्रि–परिषद द्वारा बरगी बांध, जबलपुर में 30 अप्रैल 2026 को क्रूज दुर्घटना के कारण हुई जनहानि की न्यायिक जाँच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय जबलपुर श्री संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग गठित किये जाने के संबंध में 10 मई 2026 को जारी आदेश का अनुसमर्थन किया गया।

मुंबई की लाइफ लाइन रहे डिब्बावालों का वजूद संकट में

- हार्वर्ड ने कभी लॉजिस्टिक्स का मास्टरक्लास बताया था, प्रिंस चार्ल्स खुद देखने आए थे

मुंबई (एजेंसी)। जब मुंबई पूरी तरह जागी भी नहीं होती, सफेद टोपी और कुर्ते में कुछ लोग साइकिलों पर ऊंचे-ऊंचे टिफिन के ढेर लेकर रेलवे स्टेशनों पर पहुंच जाते हैं। ट्रेन में चढ़ते हैं, शहर पार करते हैं और फिर पैदल या साइकिल से घर का बना गरम खाना दफ्तरों तक पहुंचाते हैं। ये हैं मुंबई के डिब्बावाले- एक ऐसी व्यवस्था, जिसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने कम लागत के लॉजिस्टिक्स का मास्टरक्लास बताया और जिसे देखने 2003 में तत्कालीन प्रिंस चार्ल्स खुद मुंबई आए थे। लेकिन आज यही डिब्बावाले वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। डिब्बावाला व्यवस्था की शुरुआत 19वीं सदी के आखिर में हुई, जब ब्रिटिश राज के दौरान बॉम्बे (अब मुंबई) तेजी से फैल रहा था। दफ्तर जाने वाले लोगों को घर का खाना चाहिए था।

कोरोना आया और सब बदल गया

फिर कोरोना आया और सब बदल गया। दफ्तर बंद हुए, वर्कफ्रॉम होम शुरू हुआ और टिफिन की जरूरत अचानक खत्म हो गई। रिपोर्ट में मुंबई टिफिन बॉक्स सप्लायर्स एसोसिएशन के सचिव किरण गवंडे के हवाले से कहा गया है, 'लॉकडाउन के बाद से कई लोग हफ्ते में सिर्फ 2–3 दिन दफ्तर जाते हैं। इसका डिब्बावालों पर बड़ा असर हुआ। 2018 में जो संख्या 4,500 थी, वह अब 1,500 रह गई है।' जो बचे हैं, उनकी हालत भी अच्छी नहीं हैं। बालू शिंदे 20 साल तक डिब्बावाला रहे। रोज 15–20 टिफिन पहुंचाते थे। हर माह 20,000 रुपए कमाते थे। 2020 के अंत तक सिर्फ दो ग्राहक बचे। अब वे ऑटो चलाते हैं। जो टिके हैं, वे दो–दो काम कर रहे हैं। एसोसिएशन अब शिफ्ट आधारित काम की योजना बना रही है। लेकिन अध्यक्ष रामदास कार्वांडे कहते हैं, 'अभी तो चल रहा है, लेकिन आगे क्या होगा, कह नहीं सकते।' हर सुबह मुंबई की ट्रेनों में स्टील के टिफिन लिए ये लोग अब भी दिखते हैं।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने मंदिर में किए दर्शन

- माता-पिता और पत्नी भी साथ, बोले-पांच राज्यों में सफल चुनाव के बाद आशीर्वाद लेने आया

आगरा (एजेंसी)। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आगरा पहुंचे हैं। मंगलवार सुबह 6.30 बजे उन्होंने पत्नी और माता-पिता के साथ कैलाश महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना की। पिता का हाथ थामकर आरती की। दुग्धाभिषेक किया। करीब 45 मिनट तक मंदिर में रहे। मंदिर के बाहर मीडियाकर्मियों से मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा- पांच राज्यों (प. बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरलम, पुडुचेरी) में सफल चुनाव संपन्न होने के बाद पत्नी अनुराधा के साथ आगरा आया हूं। पिता और मां का आशीर्वाद लिया, इसके बाद महादेव की पूजा की। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव भी पारदर्शी होंगे।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ बुधवार, 03 जून 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

रक्षाबंधन पर बहनें करेंगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन की बसों में सफर: मुख्यमंत्री

परिवहन सेवा को चरणबद्ध रूप से किया जाएगा शुरू

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य परिवहन सामान्य जन के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य सरकार न सिर्फ प्रदेश में बेहतर और आधुनिक सड़कों का तेजी से निर्माण कर रही है, बल्कि जल्द ही नागरिकों को राज्य परिवहन की विशेष सुविधा भी देने जा रही है। राज्य सरकार चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत की ओर बढ़ रही है। इस बार रक्षाबंधन पर हमारी बहनें परिवहन विभाग की बसों में सफर करें, इसके लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने यह जानकारी विधानसभा में मीडिया से चर्चा में दी।

राज्य सरकार जन सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति के कारण शहरों के बीच दूरी अधिक है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा सभी समस्याओं को खत्म कर जनता का आवागमन सुगम बनाएगी। उम्मीद है कि राज्य के अंदरूनी हिस्सों और पड़ोसी राज्यों के साथ मध्यप्रदेश सरकार का यह प्रयास सुगम परिवहन सेवा के प्रभावी रूप में देखने को मिलेगा। प्रदेश में जन सुविधाओं के विस्तार और प्रदेश के समग्र विकास के लिए हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता और संकल्प के साथ कार्य कर रही है।

श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

मुनि संभव सागर बोले– मन की स्थिरता से ही शांति, 128 अर्घ अर्पित कर सुख–शांति की कामना

भोपाल (नप्र)। भोपाल के चौक स्थित धर्मशाला में आयोजित श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान में इन दिनों भक्ति और आस्था की अनुपम बयार बह रही है। आचार्य विद्यासमयसागर महाराज के शिष्य मुनि संभव सागर महाराज के ससंघ सानिध्य में चल रहे इस धार्मिक अनुष्ठान में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या उमड़ रही है।

विधान के दौरान इंद्रों द्वारा भगवान जिनेंद्र का अभिषेक किया गया, जिसके साथ शांति धारा और विशेष पूजा-अर्चना संपन्न हुई। श्रद्धालुओं ने विधान मंडल पर 128 अर्घ अर्पित कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना की।

इस अवसर पर धर्मसभा को संबोधित करते हुए मुनि संभव सागर महाराज ने कहा कि संसार में प्राणी के दुखों का मूल कारण उसका चंचल और भटकता हुआ मन है। जब मन सांसारिक मोह-माया में उलझता है, तब व्यक्ति परेशानियों से

घिर जाता है। उन्होंने कहा कि जीवन में सुख और शांति प्राप्त करने के लिए मन को स्थिर करना आवश्यक है। मन की स्थिरता ही आत्मा को परमात्मा और भगवत्ता से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करती है।

विधान के प्रवक्ता अंशुल जैन ने बताया कि इस अनुष्ठान के पुण्यार्जक परिवार श्रीमती पांचूबाई, सुहागमल जैन एवं ऋषभ-मंजू जैन द्वारा विधान मंडल पर प्रमुख क्रियाएं संपन्न की गईं।

कार्यक्रम में प्रमुख पात्रों के रूप में सो धर्म इंद्र, प्रियंका, महेंद्र, कुबेर, आशा, विजेंद्र उपस्थित रहे। वहीं ध्वजारोहण का दायित्व विनोद, विपिन (एमपीटी) ने निभाया। शांति धारा मनोज-प्रीति बांगा द्वारा की गई, जबकि महाज्ञानायक की भूमिका प्रतिभा-सचिन और यज्ञनायक के रूप में पूर्ति-शशांक ने अर्घ अर्पित किए।

संक्षिप्त समाचार

सलीम डोला ड्रग्स केस में ईडी का बड़ा ऐक्शन

- महाराष्ट्र-गुजरात में छापेमारी, दाउद इब्राहिम का है सहयोगी

मुंबई (एजेंसी)। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र और गुजरात में कई जगहों पर छापेमारी की है। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि यह छापेमारी हाल में तुर्किये से भारत वापस लाए गए मादक पदार्थ तस्कर मोहम्मद सलीम डोला के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई। ईडी के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी की ओर से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला

दर्ज किए जाने के बाद मुंबई और गुजरात के सूरत और अंकलेश्वर (भरूच जिला) में लगभग 20 स्थानों पर छापेमारी की गई। डोला उर्फ सलीम इस्माइल डोला को वैश्विक स्तर पर वांछित आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का करीबी सहयोगी बताया जाता है और मादक पदार्थ निरोधक एजेंसियों ने उस पर एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह संचालित करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। डोला (59) को अप्रैल में तुर्किये से वापस भारत लाया गया था और दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। ईडी अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी की यह कार्रवाई उन परिसरों में की जा रही है जो रासायनिक पदार्थों के आपूर्तिकर्ताओं, रासायन के व्यापार में लगे बिचौलियों, कृत्रिम मादक पदार्थ मेफेड्रोन (एमडी) के निर्माण और वितरण में शामिल तस्करों, हवाला संचालकों और संगठित मादक पदार्थ गिरोह से प्राप्त धन से अर्जित बेनामी संपत्ति के मालिकों से संबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला डोला और अन्य लोगों से जुड़ा है।

किसी की कोई बपौती नहीं, बंगला खाली होगा

- सीएम सम्राट का राबड़ी को जवाब बोले- ये राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है

मुजफ्फरपुर (एजेंसी)। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास खाली करने के विवाद के मामले को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह राजतंत्र नहीं, लोकतंत्र है। यहां किसी की कोई बपौती नहीं है। बंगला खाली होगा। अगर कोई गुंडा गर्दी करेगा तो उसको पकड़कर जेल में डाला जाएगा। मुजफ्फरपुर में आयोजित

सहयोग शिविर को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों को लगता है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन कभी किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि, मैं पिछले 10 वर्षों में कई बार मंत्री और उपमुख्यमंत्री बना, गृह मंत्री भी बना, लेकिन सरकारी घर में नहीं रहा। अपने निजी आवास में रहा।

नीतिश कुमार को सीएम सम्राट ने दिया धन्यवाद– सीएम सम्राट चौधरी ने नीतिश कुमार को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें कोई नोटिस नहीं गया, लेकिन वह मुख्यमंत्री पद से हटते ही सीएम आवास खाली कर दूसरे आवास में चले गए। लोकतंत्र में लोग उसे देखना चाहते हैं जो जनता के सेवक होते हैं। मैंने मुख्यमंत्री आवास के सामने लोक सेवक का आवास भी लिखवा दिया है। सभा को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकतंत्र में सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं होता है।

मुर्दा ढोने वाली सरकारी गाड़ी में चुराता था बकरियां

गांव वालों ने किया पीछा, संजय गांधी अस्पताल का ड्राइवर गिरफ्तार

रीवा (नप्र)। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक ऐसा हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने स्वास्थ्य विभाग की सुरक्षा और कार्यप्रणाली की पोल खोलकर रख दी है। रीवा के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल के एक शासकीय शव वाहन का इस्तेमाल शवों को ले जाने के बजाय आधी रात को बकरियां चुराने के लिए किया जा रहा था। इस अजीबोगरीब और गंभीर वारदात का खुलासा तब हुआ जब गुढ़ थाना पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से मुख्य आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर सरकारी गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया।

आधी रात को एम्बुलेंस देख चौंके ग्रामीण– यह पूरा मामला गुढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पोखरा का है। बीते 28 मई की रात को फरियादी का परिवार घर के अंदर सो रहा था और उनकी 6 बकरियां बाहर बंधी हुई थीं। इसी दौरान अस्पताल का ड्राइवर राजेश मिश्रा अपने साथियों के साथ सरकारी शव वाहन लेकर गांव पहुंचा। एम्बुलेंस जैसी दिखने वाली इस गाड़ी को देखकर शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन जब आरोपियों ने बकरियों को गाड़ी के अंदर ठूंसना शुरू किया,

तो आहट पाकर घर वाले जाग गए। ग्रामीणों ने दूर तक उस गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन आरोपी बकरियों को लेकर भागने में सफल रहे। इसके बाद पीड़ित ने थाने में केस दर्ज कराया।

सीधी जिले से बरामद हुई बकरियां– मामले की जांच के दौरान पुलिस को ग्रामीणों ने बताया कि वारदात में एम्बुलेंस जैसी गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था। कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस जब संजय गांधी अस्पताल के ड्राइवर राजेश मिश्रा तक पहुंची और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की गई सभी 6 बकरियों को सीधी जिले के रामपुर नैकिन स्थित पिपराव गांव से सकुशल बरामद कर लिया है। मामले में ड्राइवर राजेश मिश्रा और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। पुलिस ने इस गंभीर लापरवाही को लेकर अस्पताल प्रबंधन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) को सख्त पत्र लिखा है।

अन्नामलाई ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात

दावा-बीजेपी से सम्मानजनक विदाई चाहते हैं, 7 जून को फैसला लेंगे

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने मंगलवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने सुबह में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष से भी मुलाकात की थी। यह मुलाकात उनके बीजेपी छोड़ने की चर्चाओं के बीच हुई है। सूत्रों के मुताबिक, वह भाजपा से बिना टकराव वाली सम्मानजनक विदाई चाहते हैं। इसके बाद वह

तमिलनाडु में 'राष्ट्रवादी-तमिल दर्शन' आधारित गैर-राजनीतिक आंदोलन शुरू करेंगे, जिसे जनभावनाओं के आधार पर बाद में राजनीतिक दल में बदला जा सकता है। अन्नामलाई 7 जून को अपने कोर समर्थकों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वह आगे की रणनीति का ऐलान कर सकते हैं। युवा वोटबैंक में उनकी पकड़ को देखते हुए उनके अगले कदम पर राजनीतिक दलों की नजर है। यह भी चर्चा है कि संगठन चाहता है कि अन्नामलाई ऐक्टिव रहें।

अन्नामलाई और बीजेपी में अनबन, 4 संकेत...

विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अन्नामलाई की जगह नैनार नागेंद्रन को तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में अन्नामलाई ने चुनाव भी नहीं लड़ा था। अन्नामलाई ने तीन–भाषा नीति को मौजूदा सत्र से लागू करने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय से इसे 2029–30 शैक्षणिक सत्र से लागू करने की मांग की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एआईए डीएमके के साथ बीजेपी के गठबंधन को लेकर अन्नामलाई सहमत नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने एनडीए के लिए चुनाव प्रचार किया था। राजनीतिक विश्लेषक सुमंत सी. रमन के मुताबिक, अन्नामलाई की एन मन्न, एन मक्कल पदयात्रा के बाद तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 11 फीसदी तक पहुंचा था।

मुझे इस औरत ने बहुत परेशान कर दिया

- रतलाम में युवक ने सुसाइड से पहले वीडियो बनाया बोला- पत्नी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी

रतलाम (नप्र)। रतलाम में युवक ने सुसाइड कर लिया। इससे पहले उसने बाइक चलाते हुए मोबाइल से वीडियो बनाया। इसमें पत्नी, साली और उसके पति पर आरोप लगाए। कहा- पत्नी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। परेशान होकर जान दे रहा हूं।

मामला कालूखेड़ा के सेमलिया गांव का है। यहां रहने वाले राकेश चौहान (33) ने सोमवार शाम करीब साढ़े 6 बजे नीम के पेड़ से फांसी लगा ली। आरोप लगाने का वीडियो मंगलवार को सामने आया है। राकेश देर रात कर घर नहीं पहुंचा तो परिजन उसे ढूंढने निकले। रात करीब साढ़े 8 बजे उसका शव पेड़ से लटका मिला। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

वीडियो में कहा- जिंदगी से परेशान हो गया हूं- वीडियो में राकेश ने कहा- आज मैं फांसी लगाकर मर रहा हूं। इसके जिम्मेदार रीना और उसका पति अंतर सिंह राठौड़ हैं। इनके भड़काने पर मेरी पत्नी रूबी ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद की है। अब मैं अपनी इच्छा से मरने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं इस जिंदगी से परेशान हो गया हूं।

मेरे को इस औरत ने बहुत परेशान किया है। जिस दिन भी इसे चाहिए मैंने 2 हजार, 5 हजार रुपए से लेकर लाखों रुपए की मांगें पूरी कीं। अभी 8 दिन पहले कहा कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। मैंने नीलम चौहान के खाते में पैसे डाले हैं। मेरा खाता चेक कीजिएगा, उसने मुझसे रुपए डलवाए हैं। अब मैं मरूंगा। मरने के बाद मेरी संपत्ति का मालिक मेरा लड़का सूर्या चौहान होगा।

परिजन ने पत्नी समेत 3 के खिलाफ शिकायत दी- मंगलवार सुबह राकेश के परिजन कालूखेड़ा थाना पहुंचे। राकेश ने वीडियो में जिन लोगों का नाम लिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई का आवेदन दिया। फिर गांव के श्मशान में उसका अंतिम संस्कार किया।

पुलिस बोली- मामले की जांच कर रहे- कालूखेड़ा थाना प्रभारी शंकर सिंह चौहान ने बताया कि राकेश और रूबी की शादी 2005 में हुई थी। दोनों के बीच लंबे समय से तलाक का केस चल रहा है। रूबी ने पति राकेश के खिलाफ मारपीट की स्रढ्रक्र भी दर्ज कराई थी।आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामला जांच में लिया है।

- जेंडर बदलवाने के लिए 8 लाख का लोन लिया, विरोध के बाद दोनों फरार

सरकारी टीचर ने फुफेरी बहन को 'राहुल' बनवाया, शादी की

जमुई (एजेंसी)। बिहार के जमुई जिले में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार बोर्ड से चयनित सरकारी टीचर नयनश्री कुमारी ने अपनी फुफेरी बहन राखी कुमारी का जेंडर चेंज कराने के बाद उससे मंदिर में शादी कर ली। नयनश्री ने जेंडर चेंज के लिए कथित रूप से 8 लाख रुपए का लोन भी लिया था। नयनश्री और जेंडर चेंज के बाद राहुल (राखी) से शादी की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद दोनों परिवारों के बीच विवाद शुरू हो गया।

पटेश्वर नाथ मंदिर में हुई शादी

नयनश्री (22) और राहुल (24) ने जमुई के लक्ष्मीपुर के पटेश्वर नाथ मंदिर में 31 मई 2026 को शादी की। शादी के दौरान सीमित संख्या में लोग मौजूद थे। मंदिर में वरमाला और अन्य धार्मिक रस्मों के बाद दोनों ने एक–दूसरे को जीवनसाथी के रूप में स्वीकार किया। शादी के बाद दोनों राहुल के गांव पहुंचे, जहां हिंदू परंपरा के अनुसार कई रस्में भी निभाई गईं।

- **पटना में रहकर बढ़ी नजदीकियां–** 2023 में नयनश्री और राखी (अब राहुल) ने परीक्षा की तैयारी करने का फैसला किया। इसके लिए दोनों पटना जाकर पढ़ाई करना चाहते थे। दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध थे, इसलिए परिजन ने दोनों बहनों को साथ में पढ़ाई के लिए पटना भेज दिया। 2025 में नयनश्री ने परीक्षा पास की। इसके बाद उनका चयन –3 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत हुआ। चयन के बाद उन्होंने नौकरी जॉइन कर ली। अभी वे लक्ष्मीपुर के प्राइमरी स्कूल मेदनीपुर में पोस्टेड हैं।
- **8 लाख रुपए लोन लेकर राखी का जेंडर चेंज कराया–** वार्ड सदस्य राजेश ने बताया, राखी कुमारी ने करीब 6 महीने पहले जेंडर ट्रांजिशन की प्रक्रिया पूरी की थी। इसके लिए नयनश्री ने अपने नाम पर बैंक से लगभग 8 लाख रुपए का लोन लिया था। नयनश्री का मानना था कि वह सरकारी शिक्षिका हैं, इसलिए अगर वो खुद जेंडर ट्रांजिशन करातीं, तो नौकरी में कुछ दिक्कतें आ सकती थीं। उन्होंने आगे कहा, इसी वजह से नयनश्री ने राखी को जेंडर ट्रांजिशन कराने के लिए कहा।

दोस्ती, छुरेबाजी और नसीहत!

सीएम योगी ने खींच दी यूपी चुनाव की लकीर

- अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति को दे रहे हैं धार

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है। लखनऊ के सियासी गलियारों और मीडिया बंधुओं के बीच इसे समय से कुछ महीने पहले करवाए जाने की अटकलबाजियां भी चलने लगी हैं। इन सबके बीच गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में सूर्या चौहान हत्याकांड के आरोपियों पर जिस तरह से यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है और कर रही है, वह प्रदेश में चुनावी टोन सेट करने का एक बड़ा आधार बनता दिख रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे भारत में अपनी छवि अपराध से मुक्ति दिलाने वाले सीएम के तौर पर बनाई है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, पिछले 9 वर्षों से ज्यादा के उनके शासन काल में जिस तरह से दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ

यूपी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, वह आम जनता को पसंद आता है, यह कहने में निष्पक्ष से निष्पक्ष व्यक्ति को भी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। गाजियाबाद का सूर्या चौहान हत्याकांड उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है।

अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बड़ा एजेंडा– सूर्या चौहान की बेरहमी से हत्या के मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। इस हत्याकांड के तीन आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलने की भी तैयारी है। यूपी में अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हाल के वर्षों में नई नहीं है। लेकिन, सूर्या चौहान का कत्ल और उसके कातिल दोस्त का त्वरित एनकाउंटर कई मायनों में इस संवेदनशील राज्य के लिए अहम है। असद पर आरोप था कि उसने अपने दोस्त को बकरीद के मौके पर मिलने के लिए बुलाया और उसी की बकरे की तरह कुर्बानी दे दी। यह घटना सिर्फ हृदयविदारक नहीं है, इंसानियत की दुनिया के लिए बहुत ही असमान्य और रूह कंपा देने वाला हत्याकांड है। फिर भी समाज का एक वर्ग इस एनकाउंटर पर सवाल उठाने की कोशिश से बाज नहीं आ रहा और इसी के चलते मसला बड़ा है।

सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव को हटाया

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने मंगलवार को ऑन स्क्रीन मार्किंग में विवाद के बीच सीबीएसई के चेयरमैन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया। ओएसएम सर्विस के टेंडर और खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। उधर, री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर साइबर अटैक हुआ। ओएसएम के अनुसार, 2 मिनट में 15 लाख एक्सेस अटेंप्ट हुए, जबकि 1 लाख से ज्यादा बार सिस्टम की फाइलों तक बिना अनुमति पहुंचने की कोशिश की गई। हालांकि, साइबर अटैक के बावजूद पोर्टल काम करता रहा और दोपहर तक काफी आवेदन कर दिया।

सोनम की जमानत पर हाईकोर्ट का फैसला आज, पुलिस ने दी है चुनौती

इंदौर। चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम रघुवंशी की जमानत को लेकर आज महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। मेघालय पुलिस द्वारा निचली अदालत के आदेश को चुनौती दिए जाने के बाद उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो चुकी है और अदालत आज अपना निर्णय सुनाएगी। इस फैसले से यह स्पष्ट होगा कि सोनम जमानत पर बाहर रहेगी या फिर उसे दोबारा जेल भेजा जाएगा।

राजा रघुवंशी की शिलांग में हनीमून के दौरान हत्या कराए जाने के आरोपों का सामना कर रही सोनम को जिला अदालत ने 29 अप्रैल को चौथे जमानत आवेदन पर राहत दी थी। अदालत ने गिरफ्तारी संबंधी दस्तावेजों में दर्ज त्रुटि को महत्वपूर्ण मानते हुए उसे जमानत प्रदान की थी। इसके बाद मेघालय पुलिस ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया। सुनवाई के दौरान मेघालय सरकार की ओर से महाधिवक्ता ए. कुमार के साथ

राजा रघुवंशी हत्याकांड में जमानत बनी रहेगी या होगी निरस्त

अधिवक्ता एम खेरा, आर खारक्रांग और ए मलिक ने पक्ष रखा। सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि सोनम को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों की पूरी जानकारी थी और उसकी गिरफ्तारी विधिसम्मत तरीके से की गई थी।

लिपिकीय त्रुटि जमानत का आधार नहीं

सरकारी वकीलों ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी दस्तावेजों में केवल लिपिकीय त्रुटि हुई थी। दस्तावेज में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के स्थान पर गलती से धारा 403(1) अंकित हो गई थी, जबकि इस संहिता में धारा 403 का कोई प्रावधान ही नहीं है। सरकार का तर्क था कि इतनी गंभीर प्रकृति के अपराध में केवल इस त्रुटि को आधार बनाकर जमानत देना उचित नहीं माना जा सकता। दूसरी ओर सोनम की ओर से अधिवक्ता एस छापा और एस चंदा अदालत में अपना पक्ष रखेंगे। बचाव पक्ष का कहना है कि गिरफ्तारी के समय आरोपी को सही कानूनी जानकारी नहीं दी गई थी, जिससे उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। इसी आधार पर जिला अदालत ने जमानत मंजूर की थी।

अन्य आरोपियों को राहत नहीं

मामले के अन्य आरोपियों को राहत नहीं मिली है। आरोपी राज कुशवाह, आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत और विशाल राजपूत की जमानत याचिकाएं पहले ही खारिज की जा चुकी हैं और वे वर्तमान में जेल में बंद हैं। वहीं, साक्ष्य मिटाने के मामले में इंदौर से गिरफ्तार किए गए तीन आरोपी जमानत पर हैं सोनम को जमानत मिलने के बाद भी अदालत ने शिलांग छोड़ने की अनुमति नहीं दी है। अब सभी की नजरें उच्च न्यायालय के फैसले पर टिकी हैं, जो यह तय करेगा कि जिला अदालत का आदेश कायम रहेगा या सोनम की जमानत निरस्त कर दी जाएगी।

चरनोई भूमि से अतिक्रमण हटाया

इंदौर। तहसील मल्हारगंज के ग्राम बांक में शासकीय चरनोई भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई सर्वे क्रमांक 182 एवं 187/1 की लगभग 1.500 हेक्टेयर भूमि पर की गई। कार्रवाई के दौरान टीन शेड से निर्मित गैरेज, ऑटो पार्ट्स तथा वाहन सर्विसिंग से संबंधित लगभग 35 दुकानों को हटाया गया। संबंधित भूमि को कलेक्टर इंदौर द्वारा धार रोड थाना, जनपद पंचायत इंदौर तथा फायर स्टेशन के लिए आवंटित किया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रशासन, पुलिस एवं नगर निगम की रिमूवल टीम की संयुक्त उपस्थिति में संपन्न हुई। इस दौरान जनपद पंचायत इंदौर तथा ग्राम पंचायत बांक का अमला भी मौजूद रहा।

गिरने से टाइल्स कारीगर की मौत

इंदौर। लसूड़िया थाना क्षेत्र में निमार्णाधीन भवन में काम कर रहे टाइल्स कारीगर की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई। हादसा रविवार रात का बताया जा रहा है। परिजनों ने घटना के बाद सूचना देने में देरी का आरोप लगाया है। मृतक का नाम गोलू (32) पिता राजाराम बड़ोले निवासी वृंदावन कॉलोनी देवास नाका है। वह सीढ़ियों के बीच बनी खाली जगह से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक के भाई अजय के अनुसार, देर रात एक बजे गोलू को एमवाय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी गोलू के साथ काम कर रहे मजदूरों ने परिजनों को दी थी।

तीन बच्चों की मां ने फांसी लगाई

इंदौर। एक महीने पहले मायके आई तीन बच्चों की मां ने फांसी लगाकर जान दे दी। उसका विवाह 12 साल पहले आलीराजपुर में हुआ था। मृतका के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। खुदकुशी का कारण भी पता नहीं चल सका। मृतका स्कीम नंबर-136 निवासी दीपिका (32) पति दिलीप वाघेला है। लसूड़िया पुलिस ने बताया कि दीपिका रविवार दोपहर में कमरे में आराम करने गई थी। देर शाम तक वह बाहर नहीं आई तो उसकी मां ने आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पिता और छोटी बहन कमरे के पास पहुंचे। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर उन्होंने दरवाजे का लॉक तोड़ा। अंदर जाकर देखा तो दीपिका फंदे पर लटकी हुई थी। दीपिका के पति एनजीओ में काम करते हैं। आत्महत्या के पीछे पारिवारिक कलह की आशंका जताई जा रही है।

ड्रग्स के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

इंदौर। नशे के कारोबार पर शिकंजा कसते हुए क्राइम ब्रांच ने दो तस्करों से 30.02 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की है। नशाखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश में पुलिस गश्त कर रही थी। इसी दौरान टीम स्कीम नंबर 134 स्थित फरीदाबाग कब्रिस्तान के पास पानी की टंकी के पास से दो युवक दिखाई दिए, जो पुलिस को देखकर घबराने लगे। संदेह होने पर टीम ने पूछताछ की। दोनों ने अपनी पहचान देवास निवासी सरफराज उर्फ शब्बु और अमन उर्फ सलमान के रूप में बताई। सरफराज के पास से 15.10 ग्राम तथा अमन के पास से 14.92 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई।

बच्चों को सिखाया 'स्ट्रेंजर डेंजर' का सबक

इंदौर। बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस लगातार नवाचार कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने रविवार को अनूठा जागरूकता अभियान ऑपरेशन सेफ स्माइल चलाया। जहां बच्चों को सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। सहायक पुलिस आयुक्त निधि सक्सेना और थाना प्रभारी ने सादे वस्त्रों में अभियान संचालित किया। पुलिसकर्मियों ने गेम जोन में बच्चों के पास जाकर उन्हें चॉकलेट, गिफ्ट और खरगोश देने का लालच देकर साथ चलने के लिए कहा। सभी देखकर हैरान रह गए कि कई बच्चे बिना किसी पहचान, जानकारी के उन लोगों के साथ चलने को तैयार हो गए। इससे स्पष्ट हुआ कि बच्चों में अजनबियों से सतर्क रहने की समझ विकसित करना आवश्यक है। इसके बाद पुलिस ने पार्किंग क्षेत्र में बच्चों, उनके अभिभावकों और अन्य लोगों के साथ संवाद किया। बच्चों को समझाया कि वे किसी अनजान व्यक्ति से चॉकलेट, खिलौना, गिफ्ट या अन्य कोई वस्तु स्वीकार न करें और बिना माता-पिता की अनुमति किसी के साथ कहीं भी न जाएं।

ठेकेदार ने रॉड से हमला किया

इन्दौर। नरवल स्थित कृष्णा प्लास्टिक कंपनी में मजदूरी के पैसे मांगना दो मजदूरों को महंगा पड़ गया। ठेकेदार ने अपने साथी के साथ मिलकर दोनों मजदूरों पर रॉड से हमला किया। बाणगंगा पुलिस ने भवानी नगर निवासी घायल मजदूर नरेंद्र पिता ऋतुराज चौहान की शिकायत पर आरोपी ठेकेदार राजेश निगम और उसके साथी बिरजू के खिलाफ केस दर्ज किया है। फरियादी ने बताया कि जब ठेकेदार से बकाया रुपए मांगे तो आरोपी ने मारपीट कर दी।

पिस्टल सहित पकड़ाया - बड़ी वारदात की नीयत से घुम रहे बदमाश को कनाड़िया पुलिस ने पिस्टल और दो जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा। कनाडिया पुलिस द्वारा चाकूबाजों और आदतन अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत सूचना पर इंदौर पब्लिक स्कूल ईस्टर्न कैंपस के सामने से अनिकेत पिता भैरूसिंह चौहान निवासी सब्जी मंडी के सामने बंगाली कॉलोनी को पकड़ा।

चोरी के दो ऑटो रिक्शा बरामद

इंदौर। खजराना पुलिस ने शातिर चोर से दो ऑटो रिक्शा बरामद किए हैं। थाना प्रभारी द्वारा रिंगरोड से लगी आउटर कॉलोनियों, भीड़भाड़ वाले स्थानों, रहवासी सोसायटियों और मल्टियों में वारदातों को रोकने टीम का गठन किया गया था। टीम को फरियादी मोइनुद्दीन पिता हुसैनुद्दीन खान निवासी सुपर पैलेस कालोनी खजराना ने बताया कि 26 मई की रात 11.30 बजे उन्होंने अपना पैसेंजर आटो घर के सामने खड़ा किया था। अगली सुबह घर के सामने आटो नहीं दिखा। फरियादी की शिकायत के बाद पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। फुटेज के आधार पर फरीद पिता चांद खान निवासी मदीना मस्जिद के पास चंदन नगर को पकड़ा। फरीद ने कबूल किया कि वह अपने शौक पूरे करने के लिए चोरी करता था। उसकी निशानदेही पर आटो रिक्शा (एमपी-09-आरए-7551) और (एमपी-09-आईए-5967) जब्त की।

उत्पाती 17 छात्रों को 25 हजार रु जमा करने पर ही मिलेगा रिजल्ट

इंदौर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी अध्ययन संस्थान के छात्रावास में अर्धनग्न होकर नृत्य करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मामले में चिन्हित 17 विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम फिलहाल रोक दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रत्येक दोषी विद्यार्थी को 25 हजार रुपये की दंड राशि जमा करने के बाद ही उसका परिणाम जारी किया जाएगा। संस्थान के निदेशक डॉ प्रतोष बंसल ने बताया कि घटना को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए यह निर्णय लिया गया है। दोषी विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी बुलाया जा रहा है। अब तक 5 विद्यार्थियों के अभिभावक संस्थान पहुंच चुके हैं। इनमें से केवल एक विद्यार्थी ने 25 हजार रुपये की दंड राशि जमा की है। शेष विद्यार्थियों को भी निर्धारित राशि जमा करना होगी, तभी उनका परिणाम जारी किया जाएगा।

वीडियो से पहचाने गए छात्रों के अभिभावकों को बुलाया गया

जून मध्य में परीक्षा संभावित

घटना में शामिल अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के कुछ प्रश्न पत्र शेष थे। छात्रावास में हुए हंगामे के बाद उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई थी। अब विश्वविद्यालय प्रबंधन इन विद्यार्थियों की शेष परीक्षा जून के मध्य, लगभग 15 जून के आसपास आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। परीक्षा, दंड राशि, परिणाम रोकने तथा परीक्षा से वंचित रखने संबंधी निर्णय जांच समिति की अनुशंसा पर लिए गए थे।

संपत्ति को पहुंचाया नुकसान

प्रकरण रामानुजन छात्रावास का है, जहां अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों ने देर रात जमकर हंगामा किया था। विद्यार्थियों ने छात्रावास परिसर में अर्धनग्न होकर डांस किया और परिसर की कई वस्तुओं को नुकसान पहुंचाया। तोड़फोड़ के दौरान मेज-कुर्सियां, पानी की टंकी और खिड़कियों के कांच क्षतिग्रस्त कर दिए गए थे। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया। वीडियो की जांच के आधार पर 17 विद्यार्थियों की पहचान की गई और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई। अब प्रबंधन दंडात्मक कार्रवाई के साथ-साथ परीक्षा और परिणाम संबंधी प्रक्रिया भी तय कर रहा है।

मोबाइल अपडेट के बाद खाते से उड़े 1.93 लाख, ऑनलाइन ठगी

सिस्टम अपडेट का संदेश आया, क्लिक करते ही परेशानी

इंदौर। हीरा नगर क्षेत्र में एक निजी लॉजिस्टिक कंपनी के कर्मचारी के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। मोबाइल पर आए सिस्टम अपडेट के संदेश पर कार्रवाई करने के बाद उसके फोन में तकनीकी दिक्कत शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद जब उसने अपने बैंक खाते की जानकारी देखी तो उसमें से लगभग 1 लाख 93 हजार रुपये निकाले जा चुके थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सुखलिया निवासी अंकित गुप्ता ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है। अंकित ने बताया कि उसने जनवरी 2026 में नया मोबाइल खरीदा था। 15 मई को उसके मोबाइल पर सिस्टम अपडेट का संदेश आया, जिसके बाद उसने फोन को अपडेट कर लिया।

अपडेट से तकनीकी दिक्कत- अंकित के मुताबिक अपडेट के बाद मोबाइल की कुछ सुविधाएं ठीक तरह से काम नहीं कर रही थीं। समस्या दूर करने के लिए उसने एक अन्य अनुप्रयोग डाउनलोड किया। इसके बाद दो दिन तक मोबाइल सामान्य रूप से चलता रहा, लेकिन 18 मई को फिर से तकनीकी परेशानी शुरू हो गई और कुछ ही समय में फोन पूरी तरह बंद हो गया। अगले दिन, 19 मई को वह मोबाइल को मरम्मत के लिए सेवा केंद्र पर छोड़कर आया। शाम को जब मोबाइल वापस मिला तो उसने बैंक खाते की शेष राशि जांची। खाते की जानकारी देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि उसमें से करीब 1 लाख 93 हजार रुपये ऑनलाइन स्थानांतरित किए जा चुके थे।

35 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने किया सामूहिक योग, बना रिकॉर्ड

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों में आयोजित योग महोत्सव

इंदौर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के अंतर्गत आयुष मंत्रालय द्वारा देशभर में आयोजित किए जा रहे योग महोत्सव और काउंटडाउन कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ इंदौर से हुआ। नेमावर रोड स्थित मालवांचल यूनिवर्सिटी परिसर में सोमवार को विशाल सामूहिक योग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 35 हजार से अधिक विद्यार्थियों, प्राध्यापकों और नागरिकों ने एक साथ योगाभ्यास कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया।

कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के योग गुरु एवं एस व्यासा यूनिवर्सिटी के कुलगुरु पद्मश्री डॉ. एच.आर. नागेन्द्र मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार, नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, संस्थान के संचालक सुरेश सिंह भदौरिया, डॉ. मयंक भदौरिया तथा डॉ. दीप्ति सिंह हाड़ा सहित अनेक गणमान्य जन मौजूद रहे। अमलतास एवं इंडेक्स समूह के शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी, सामाजिक संगठनों के

प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान

अपने संबोधन में पद्मश्री डॉ. एच.आर. नागेन्द्र ने कहा कि योग के प्रति लोगों की बढ़ती आस्था और रुचि के कारण आज यह पूरी दुनिया में फैल चुका है। भारत में लगभग 30 करोड़ लोग योग से जुड़े हुए हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश देश का हृदय स्थल है और इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में देश का अग्रणी शहर है। ऐसे में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को योग से जोड़ने का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि मध्य प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में योग को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, ताकि युवा पीढ़ी इसके लाभों से सीधे जुड़ सके और स्वस्थ जीवनशैली को अपनाए।

इंदौर की अनन्या अवस्थी बनीं ओडिशा के राज्यपाल की पहली महिला एडीसी

कटक की पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त ने संभाली नई जिम्मेदारी

भुवनेश्वर। ओडिशा के प्रशासनिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। इंदौर की मूल निवासी और वर्ष 2022 समूह की भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी अनन्या अवस्थी ने राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति के एड-डी-कैंप (एडीसी) के रूप में अपना पद ग्रहण कर लिया है। इस पद पर वे ओडिशा की पहली महिला पुलिस अधिकारी हैं। अनन्या अवस्थी सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आशुतोष अवस्थी की सुपुत्री हैं और उन्होंने भोपाल के राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की है। राजभवन और लोकभवन में आयोजित एक गरिमामयी और औपचारिक समारोह के दौरान राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति ने अनन्या अवस्थी को इस अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए

शुभकामनाएं दीं और उनका आत्मीय स्वागत किया। इस नई भूमिका से पहले अनन्या कटक नगरीय पुलिस जिला में सहायक पुलिस आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थीं। राजभवन में उन्होंने वर्ष 2021 समूह के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी कुलदीप मीणा का स्थान लिया है, जो अब तक राज्यपाल के पुलिस एडीसी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे।

राज्य की पहली महिला एडीसी

अपनी इस ऐतिहासिक नियुक्ति के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए अनन्या अवस्थी ने कहा कि वह राज्यपाल और ओडिशा सरकार के प्रति अत्यंत आभार प्रकट करती हैं, जिन्होंने उन्हें राज्य की पहली महिला एडीसी के रूप में काम करने का यह अनमोल अवसर प्रदान किया। उन्होंने इसे सेवा का एक बड़ा मंच बताते हुए कहा कि कार्यक्षेत्र के लिहाज से यह जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा पद है, जो उनके भविष्य के लिए काफी अच्छा अनुभव साबित होगा। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की सेवा करना उनके लिए गर्व और बहुत बड़ी जवाबदेही की बात है। व्यक्तिगत तौर पर भी यह उनके जीवन की एक अद्भुत सफलता है क्योंकि वह राज्यपाल की पहली महिला एडीसी बनी हैं।

7 बदमाश जिला बदर, 3 देंगे 6 महीने तक थाने में हाजिरी

इंदौर। शहर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने पुलिस ने प्रतिबंधात्मक आदेश किए हैं। इसके अंतर्गत सात बदमाशों को जिले से बाहर रहने तथा 3 बदमाशों को थाने में हाजिरी देने को कहा गया है। आदेश का कड़ाई से पालन नहीं होने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इमरान उर्फ बच्चा पिता गुलाम मोहम्मद निवासी गांधीग्राम खजराना थाना खजराना (अवधि 6 माह), विजय उर्फ लाला पिता महेश गोस्वामी निवासी सुविधि नगर थाना एरोड्रम (अवधि 6 माह), सुमित उर्फ सरदार पिता राजेश उर्फ राजू जरिया निवासी कुलकर्णी का भट्ठा थाना परदेशीपुरा (अवधि 6 माह), विकास उर्फ विक्का पिता नंदराम कसेरा निवासी एमजी रोड मल्हारगंज थाना (अवधि 6 माह), ऋषभ उर्फ कालू पिता रामसिंह गुर्जर निवासी अंजनी नगर थाना विजय नगर (अवधि 6 माह), राजेश उर्फ राजा उर्फ राजाबाबू पिता रामेश्वर निवासी नई बस्ती मसानिया थाना तेजाजी नगर (अवधि 3 माह) तथा विजय उर्फ बल्लू उर्फ बलिया पिता माधव सोलंकी निवासी तापी परिसर थाना चदंन नगर को 3 माह के लिए जिलाबदर किया है।

जमीन अधिग्रहण के विरोध में कलेक्ट्रेट पर किसानों का डेरा

राशन-पानी के साथ पहुंचे हजारों किसान, विरोध जताया

इंदौर। पूर्वी बायपास परियोजना और इंदौर-मनमाड़ रेल मार्ग के लिए प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के विरोध में हजारों किसानों ने मंगलवार को कलेक्टोरेट परिसर के बाहर गंजी कंपाउंड में जोरदार प्रदर्शन किया। सुबह से शुरू हुए इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान परिवारों सहित पहुंचे। महिलाओं और बच्चों की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। प्रदर्शन के दौरान एक दिव्यांग किसान ने अर्धनग्न होकर तपती सड़क पर लोट लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। भीषण गर्मी के बीच आंदोलन कर रहे किसानों में से दो की तबीयत भी बिगड़ गई, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजना पड़ा। वहीं किसान हजारीलाल को भी चक्कर आने की शिकायत हुई, हालांकि कुछ देर बाद उनकी हालत सामान्य हो गई।

मांग पूरी होने तक आंदोलन- आंदोलन में शामिल किसानों का कहना है कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पूर्वी बाईपास योजना और इंदौर-मनमाड़ रेल परियोजना के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि कई बार प्रदर्शन और ज्ञापन देने के बावजूद उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया। इसी कारण इस बार अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। किसानों ने साफ कहा कि जब तक दोनों परियोजनाओं को निरस्त नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में शामिल परिवार अपने साथ आटा, राशन और दैनिक उपयोग का सामान लेकर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि यदि आंदोलन कई दिनों तक चलता है तो भी वे पीछे नहीं हटेंगे।

धरना स्थल पर भोजन की तैयारी- सिमरोल, तिल्लौर खुर्द, फरसपुर, खुड़ैल और आसपास के गांवों से आए किसानों ने कहा कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो वे धरना स्थल पर ही भोजन बनाकर आंदोलन जारी रखेंगे। किसानों का कहना है कि यह केवल जमीन का नहीं, बल्कि उनके भविष्य और आजीविका का सवाल है। सुबह से जारी प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर बैठे रहे। कलेक्टोरेट के बाहर आंदोलनकारियों की भीड़ जुटी रही और किसानों ने प्रशासन से अपनी मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की।

संपादकीय

सीबीएसई धांधली : जिम्मेदार कौन?

देश में शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में धांधलियों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले नीट के पेपर लीक हुए, अब सीबीएसई के छात्र पहले गलत पेपर जांच के शिकार हुए तो अब रिवेल्युएशन के लिए पोर्टल न खुलने अथवा क्रैश हो जाने की समस्या से जूझ रहे हैं। यह पूरी मेहनत के साथ परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों के साथ गंभीर मजाक और मानसिक संत्रास की स्थिति है। बच्चों के अभिभावक भी परेशान हो रहे हैं। दरसअल सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा के री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन प्रक्रिया मंगलवार से होनी ती। सीबीएसई के मुताबिक पोर्टल दोबारा चालू कर दिया गया है, लेकिन लॉगिन, वेरिफिकेशन और आवेदन सबमिट करने में दिक्कतें सामने आ रही हैं। छात्रों का कहना है कि लॉग इन करने पर फेल्ड शो कर रहा है। यही स्थिति सोमवार को भी थी। तब छात्रों की पोर्टल क्रैश होने की शिकायत के बाद सीबीएसई ने भरोसा दिलाया था कि किसी तकनीकी दिक्कत के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा है। मंगलवार से स्थिति सामान्य हो जाएगी और छात्र री वेल्युएशन के लिए आवेदन कर सकेंगे। लेकिन दूसरे दिन भी छात्रों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह 4 बजकर 42 मिनट पर पोर्टल खुला जरूर था, लेकिन इसके बाद छात्रों को लॉगिन करने में समस्या का सामना करना पड़ा। बाद में खुलना भी बंद हो गया। कुछ छात्रों का कहना है कि लॉगिन नहीं हो रहा तो वहीं किसी को कैप्चा भरने में दिक्कत और कइयों को उनका ऑप्शन ही नहीं मिल रहा पा रहा है। बड़ी संख्या में छात्र लॉग इन, वेरीफिकेशन और आवेदन सबमिट करने में दिक्कतें बता रहे हैं। छात्रों का यह भी कहना है कि वो अपने क्रिडेंशियल्स दर्ज कर लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम बार-बार 'फेल्ड' ही दिखा रहा है। कई छात्रों ने दावा किया कि उनकी आंसर शीट्स में कुछ प्रश्नों की जांच नहीं हुई है या सही आंसर शीट्स होने के बावजूद नंबर नहीं दिए गए. कुछ छात्रों ने यह भी पूछा कि ऐसी स्थिति में पुनर्मूल्यांकन के दौरान कौन-सा विकल्प चुनना चाहिए, क्योंकि पोर्टल पर इससे जुड़ा स्पष्ट विकल्प मौजूद नहीं है। इस बीच यह मुद्दा अब राजनीतिक रंग भी लेता जा रहा है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने सीबीएसई पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा, एक और दिन, एक और उपलब्धि। इस बीच शिकायतों से परेशान सीबीएसई ने कहा है कि जिन उम्मीदवारों को लॉगिन में परेशानी आ रही है, वो सीधे बोर्ड को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर छात्रों और अभिभावकों की शिकायतों के बाद जागे केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सीबीएसई से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट सीबीएसई से मांगी है। साथ ही इस संबंध में आंतरिक जांच भी शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि इस वर्ष सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा में लगभग 18 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था। छात्रों को अपनी स्कैन की गई आंसर शीट्स देखने के लिए 19 मई को ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराया गया था, लेकिन पहले ही दिन वेबसाइट तकनीकी समस्याओं के कारण ठप हो गई। इसके चलते बड़ी संख्या में छात्र आवेदन नहीं कर सके। इसे देखते हुए बोर्ड ने पहले आवेदन की अंतिम तिथि 22 मई तक बढ़ाई, लेकिन दिक्कतें जारी रहने पर इसे आगे बढ़ाकर फिर 23 मई कर दिया गया। इसके बाद भी हालात नहीं सुधरे। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि लाखों बच्चों के भविष्य और भावनाओं के साथ हो रहे इस खुलेआम खिलवाड़ के लिए जिम्मेदार कौन है। और जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी?

डरा रहा है, 'सुपर अल नीनो', हमारी तैयारी क्या?

'सुपर अल नीनो' की आहट, कमजोर मानसून का खतरा और इनसे निपटने की देश की आधी-अधूरी तैयारी ने हमारे सामने कुछ बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 'कोविड 19' या हाल के खाड़ी संकट से उपजे हाहाकार को देखें तो पता चलता है कि हम आपदाओं को तब ही महत्व देते हैं जब वे हमारे सिर पर खड़ी हो जाती हैं। क्या यही कारनामा हम 'सुपर अल नीनो' से निपटने के लिए भी करने वाले हैं?

नजरिया

अमन नग्र

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

दुनियाभर के मौसम वैज्ञानिक इस समय प्रशांत महासागर को बेहद चिंता के साथ देख रहे हैं। ताजे क्लाइमेट मॉडल संकेत दे रहे हैं कि भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में एक मजबूत 'अल नीनो' तेजी से विकसित हो रहा है। समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक ऊपर जा सकता है। इतना बड़ा विचलन किसी सामान्य 'अल नीनो' का नहीं, बल्कि 'सुपर अल नीनो' जैसी स्थिति का संकेत माना जाता है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि समुद्र की सतह के नीचे भी असामान्य रूप से गर्म पानी जमा है, जो आने वाले महीनों में इस प्रणाली को और ताकत दे सकता है। अनुमान है कि यह प्रभाव नवंबर-दिसंबर 2026 के दौरान अपने चरम पर पहुंच सकता है।

भारत के लिए यह खबर केवल मौसम विज्ञान की एक तकनीकी सूचना भर नहीं है। यह उस देश के लिए चेतावनी है जिसकी खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जल-संसाधन और करोड़ों लोगों की आजीविका अब भी मानसून पर टिकी हुई है। भारत में बारिश केवल मौसम नहीं बदलती, यह बाजार का मूड बदलती है, सरकारों की चिंता बदलती है और आम आदमी की रसोई तक का गणित बदल देती है।

हालांकि हर 'अल नीनो' भारत में सूखा नहीं लाता, लेकिन इतिहास यह जरूर बताता है कि जब 'एल नीनो' बहुत मजबूत होता है, तब सामान्य से कमजोर मानसून की संभावना काफी बढ़ जाती है। यही वजह है कि इस बार वैज्ञानिकों की भाषा में घबराहट भले न हो, लेकिन चिंता साफ दिखाई दे रही है।

मानसून की कमजोरी सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहती- भारत में मानसून कमजोर पड़ने का मतलब सिर्फ बारिश कम होना नहीं होता। इसका मतलब है खेतों में देर से बुआई, सिंचाई पर बढ़ता खर्च, जलाशयों का खाली होना, बिजली की बढ़ती मांग और बाजारों में महंगाई का धीरे-धीरे चढ़ना।

मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े कृषि राज्यों में खेती का बड़ा हिस्सा आज भी सीधे मानसून पर निर्भर है। यदि बारिश का सिस्टम बिगड़ा, लंबे 'ड्राई स्पेल' बने या मानसून बार-बार 'ब्रेक' लेने लगा, तो सबसे पहला झटका खेती को लगेगा। धान, सोयाबीन, दालें, गन्ना और पशुपालन तक प्रभावित हो सकते हैं।

लेकिन चिंता यहीं खत्म नहीं होती। कमजोर मानसून का असर शहरों तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता। पानी की कमी बढ़ती है, बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती है, और खाद्य महंगाई आम आदमी की जेब पर दबाव डालने लगती है। सब्जियां, दालें, दूध और खाद्य

तेल महंगे होने लगते हैं। ग्रामीण आय घटती है तो बाजार में मांग भी कमजोर पड़ती है।

ऑटोमोबाइल से लेकर 'एफएमसीजी' (फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानि 'तेज़ी से बिकने वाले उपभोक्ता सामान') तक पूरा उपभोक्ता बाजार इसका असर महसूस करता है। पेट्रोल, डीजल और गैस की महंगाई से पहले ही लोगों की कमर टूटी हुई है, अगर 'सुपर अल नीनो' का असर वैसा ही रहा जैसी आशंका है, तो देश गंभीर आर्थिक, सामाजिक संकट में पड़ सकता है।

हालांकि विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आज की भारतीय अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में मानसून के झटकों को बेहतर तरीके से संभाल सकती है। सेवा क्षेत्र, उद्योग और शहरी अर्थव्यवस्था अब कहीं ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खतरा टल गया है। खेती और जल-संसाधन आज भी भारत की सबसे संवेदनशील कड़ियां हैं और यही वे क्षेत्र हैं जिन पर सबसे गहरा असर पड़ सकता है।

इस बार खतरा सिर्फ सूखे का नहीं, मौसमीय असंतुलन का भी है- 'अल नीनो' का असर पूरे भारत में एक जैसा नहीं होता। आमतौर पर इसका नकारात्मक प्रभाव देश के अधिकांश हिस्सों में दिखता है, लेकिन पूर्वोत्तर भारत कई बार इसका अपवाद बन जाता है। वहां सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश की स्थिति बन सकती है, यहां तक कि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसी घटनाएं भी बढ़ सकती हैं। यानि भारत एक ही समय में दो चरम स्थितियों का सामना कर सकता है – कहीं सूखा और कहीं बाढ़।

यह वही मौसमीय असंतुलन है जिसे जलवायु परिवर्तन और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। एक तरफ भीषण गर्मी और सूखी जमीन, दूसरी तरफ अचानक अत्यधिक बारिश। यही वजह है कि अब मौसम संकट केवल 'कम बारिश' का सवाल नहीं रह गया है, बल्कि बारिश के पैटर्न के टूटने का संकट बन चुका है।

पिछले वर्षों में भारत ने देखा है कि कैसे कुछ दिनों की अत्यधिक बारिश पूरे शहर डुबो देती है, जबकि लंबे समय तक सूखा किसानों को तबाह कर देता है। 'सुपर अल नीनो' जैसी स्थिति इस अस्थिरता को और बढ़ा सकती है।

सबसे बड़ा सवाल: क्या इस बार तैयारी पहले होगी?- वैज्ञानिक कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन गंभीर तैयारी की जरूरत जरूर है। मानसून को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसके नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। यही वह जगह है जहां भारत की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है।

क्या राज्य सरकारें और एजेंसियां अभी से जलाशयों का वैज्ञानिक प्रबंधन शुरू करेंगी? क्या किसानों को समय रहते फसल की सलाह मिलेगी? क्या कम पानी वाली फसलों और 'माइक्रो इरिगेशन' को तेजी से बढ़ावा दिया जाएगा? क्या शहरों में जल-संरक्षण और पुनर्चक्रण पर आपात स्तर की तैयारी होगी? क्या बिजली और खाद्य आपूर्ति को लेकर पहले से रणनीति बनेगी?

विशेषज्ञों का मानना है कि 'पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय' और 'मौसम विभाग' के विस्तारित पूर्वानुमानों पर लगातार नजर रखना इस बार बेहद जरूरी होगा। अगले 2-3 सप्ताह के पूर्वानुमान किसानों और जल-प्रबंधन एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं।

भारत ने कोविड महामारी और वैश्विक युद्ध संकटों के दौरान यह अनुभव किया है कि देर से प्रतिक्रिया कितनी महंगी पड़ सकती है। मौसम संकट का चरित्र अलग जरूर है, लेकिन उसका असर उतना ही व्यापक हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार चेतावनी पहले से दिखाई दे रही है।

सवाल अब यह नहीं है कि मानसून कमजोर होगा या नहीं। सवाल यह है कि अगर स्थिति बिगड़ती है, तो क्या भारत इस बार पहले से तैयार मिलेगा – या फिर हमेशा की तरह संकट सिर पर आने के बाद राहत उपायों की तलाश शुरू होगी। (सप्रेस)

डिजिटल गोपनीयता को मजबूत बनाने की चुनौतियाँ

साइबर युग

डॉ. भूपेन्द्र कुमार सुल्हेरे

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

इक्कीसवीं सदी का वर्तमान दौर डिजिटल क्रांति का युग है। इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल मीडिया और स्मार्ट उपकरणों ने मानव जीवन को अभूतपूर्व सुविधाएँ प्रदान की हैं। आज बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, शासन और सामाजिक संवाद का बड़ा हिस्सा डिजिटल माध्यमों पर आधारित है। किंतु इस डिजिटल विस्तार के साथ साइबर अपराध, डेटा चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और निजता के उल्लंघन जैसी गंभीर चुनौतियाँ भी तेजी से बढ़ी हैं। परिणामस्वरूप डिजिटल गोपनीयता और साइबर सुरक्षा आज केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिक अधिकारों का महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुके हैं।

भारत विश्व की सबसे तेज़ी से विकसित होती डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, आधार, ऑनलाइन शासन सेवाएँ और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने करोड़ों लोगों को डिजिटल दुनिया से जोड़ा है। किंतु जितनी तेजी से डिजिटल विस्तार हुआ है, उतनी ही तेजी से साइबर खतरों में भी वृद्धि हुई है।

रैंसमवेयर हमले, फ़िशिंग, पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी और डेटा लीक की घटनाएँ आज आम होती जा रही हैं। साइबर अपराधी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालित तकनीकों का उपयोग करके अधिक परिष्कृत हमले कर रहे हैं। ऐसे में नागरिकों, संस्थानों और सरकारों के सामने डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बन गया है।

आज साइबर सुरक्षा केवल पासवर्ड और एंटीवायरस तक सीमित नहीं रह गई है। आधुनिक सुरक्षा तंत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और उन्नत एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले वर्षों में 'जीरो ट्रस्ट नेटवर्क' मॉडल का महत्व और बढ़ेगा, जिसमें किसी भी उपयोगकर्ता या उपकरण पर स्वतः विश्वास नहीं किया जाता, बल्कि प्रत्येक गतिविधि का सत्यापन किया जाता है। इसके अतिरिक्त रियल-टाइम थ्रेट मॉनिटरिंग और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स जैसे उपकरण संभावित साइबर हमलों को पहले ही पहचानने में सहायता कर रहे हैं।

डिजिटल सुरक्षा में वीपीएन की भूमिका- वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) आज डिजिटल गोपनीयता के सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक बन चुका है। प्रारंभ में वीपीएन का उपयोग केवल भौगोलिक प्रतिबंधों को पार करने के लिए किया जाता था, लेकिन आज यह ऑनलाइन सुरक्षा का अनिवार्य उपकरण बन गया है। वीपीएन उपयोगकर्ता और इंटरनेट के बीच एक सुरक्षित एन्क्रिप्टेड सुरंग बनाता है, जिससे डेटा को साइबर अपराधियों और अनधिकृत निगरानी से सुरक्षित रखा जा सकता है। आधुनिक वीपीएन सेवाएँ वायरगार्ड और ओपनवीपीएन जैसे उन्नत प्रोटोकॉल का उपयोग करती हैं, जो तेज़ गति और बेहतर सुरक्षा दोनों प्रदान करते हैं।

व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के साथ-साथ कंपनियाँ भी सुरक्षित रिमोट वर्किंग और संवेदनशील डेटा की सुरक्षा के लिए वीपीएन तकनीक का व्यापक उपयोग कर रही हैं। कोविड-19 के बाद बढ़े दूरस्थ कार्य वातावरण में इसकी उपयोगिता और अधिक स्पष्ट हुई है।

सरकारी पहल और नियामक ढाँचा- भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल जैसे संस्थागत तंत्र साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सरकार डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित बनाने, साइबर अपराधों की रोकथाम तथा नागरिकों को जागरूक करने के लिए लगातार नई नीतियाँ और कार्यक्रम लागू कर रही है। प्रेस सूचना ब्यूरो तथा अन्य सरकारी एजेंसियाँ समय-समय पर साइबर सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी करती रहती हैं।

कॉर्पोरेट जगत की जिम्मेदारी- आज के डिजिटल युग में केवल सरकार ही नहीं, बल्कि निजी कंपनियों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। बड़े उद्योग समूह और तकनीकी संस्थान डेटा सुरक्षा, गोपनीयता संरक्षण और साइबर जोखिम प्रबंधन पर भारी निवेश कर रहे हैं। कई संगठनों ने साइबर सुरक्षा को अपनी व्यावसायिक रणनीति का अभिन्न हिस्सा बना लिया है। सुरक्षित संचार प्लेटफॉर्म, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्टेड क्लाउड सेवाएँ और नियमित सुरक्षा ऑडिट अब कॉर्पोरेट संस्कृति का हिस्सा बनते जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि साइबर सुरक्षा में निवेश केवल तकनीकी आवश्यकता नहीं, बल्कि उपभोक्ताओं के विश्वास को बनाए रखने की अनिवार्य शर्त बन चुका है।

डिजिटल गोपनीयता और सामाजिक चेतना- साइबर सुरक्षा का प्रश्न केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक भी है। जैसे-जैसे लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी के महत्व को समझ रहे हैं, वैसे-वैसे डेटा गोपनीयता के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। नागरिक अब यह जानना चाहते हैं कि उनकी जानकारी कहाँ संग्रहित की जा रही है, उसका उपयोग कैसे हो रहा है और कौन उस तक पहुँच सकता है।

यह बढ़ती जागरूकता तकनीकी कंपनियों और सरकारी संस्थाओं पर अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का दबाव बना रही है। साथ ही विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सामाजिक संगठनों द्वारा साइबर साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार भी किया जा रहा है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नए साइबर खतरे- कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने जहाँ अनेक क्षेत्रों में क्रांति ला दी है, वहीं इसके दुरुपयोग की संभावनाएँ भी बढ़ी हैं। एआई आधारित साइबर हमले, डीपफेक तकनीक, स्वचालित फ़िशिंग और उन्नत मैलवेयर भविष्य की बड़ी चुनौतियों के रूप में उभर रहे हैं। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि एआई-संचालित साइबर हमले पारंपरिक हमलों की तुलना में अधिक तीव्र, व्यापक और प्रभावी हो सकते हैं। इसलिए साइबर सुरक्षा प्रणालियों में भी एआई आधारित रक्षा तंत्र विकसित करना समय की आवश्यकता बन गया है।

सुरक्षित डिजिटल भविष्य की दिशा में- डिजिटल गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार, उद्योग, शिक्षण संस्थानों और नागरिक समाज के बीच व्यापक सहयोग आवश्यक है। तकनीकी नवाचारों के साथ-साथ जन-जागरूकता, मजबूत कानून और प्रभावी नियमन भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। भविष्य में अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-केंद्रित डिजिटल प्रणालियाँ विकसित होंगी, जिनमें व्यक्ति को अपने डेटा पर अधिक नियंत्रण प्राप्त होगा। भविष्यसूचक विश्लेषण, वास्तविक समय निगरानी और उन्नत एन्क्रिप्शन तकनीकें साइबर खतरों के विरुद्ध मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करेंगी। डिजिटल युग अभूतपूर्व अवसरों और जटिल चुनौतियों का संगम है। जैसे-जैसे हमारी सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक गतिविधियाँ ऑनलाइन होती जा रही हैं, वैसे-वैसे डिजिटल गोपनीयता और साइबर सुरक्षा का महत्व बढ़ता जा रहा है। उन्नत वीपीएन तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुरक्षा तंत्र, सरकारी नीतियाँ और जन-जागरूकता कार्यक्रम मिलकर एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भारत की डिजिटल यात्रा तभी सफल मानी जाएगी जब तकनीकी प्रगति के साथ नागरिकों की निजता, डेटा सुरक्षा और साइबर विश्वास को भी समान रूप से महत्व दिया जाएगा। यही संतुलन एक सुरक्षित, समावेशी और आत्मनिर्भर डिजिटल भारत की आधारशिला सिद्ध होगा।

क्या सिर्फ प्रशंसा तक सीमित है पत्रकारिता का यह मंच?

इम्पैक्ट फीचर

ब्रजेश कानूनगो

लेखक स्तंभकार हैं।

समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले 'इम्पैक्ट फीचर' पिछले कुछ वर्षों में मीडिया जगत की एक सामान्य प्रवृत्ति बन गए हैं। ये ऐसे प्रायोजित पृष्ठ होते हैं जो देखने में समाचार या विश्लेषणात्मक लेख जैसे लगते हैं, लेकिन वास्तव में किसी संस्था, कंपनी, उद्योग समूह अथवा सरकार द्वारा भुगतान कर प्रकाशित कराए जाते हैं। इनका उद्देश्य केवल विज्ञापन देना नहीं होता, बल्कि किसी विचार, उपलब्धि, योजना या छवि को पाठकों तक अधिक विश्वसनीय ढंग से पहुंचाना भी होता है। आज स्थिति यह है कि केंद्र और राज्य सरकारें भी अपनी योजनाओं, उपलब्धियों और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रचार के लिए बड़े पैमाने पर इम्पैक्ट फीचर प्रकाशित करा रही हैं। अखबारों के पूरे-पूरे पृष्ठ सरकारी विज्ञापनों और उपलब्धियों के बखान से भर जाते हैं। प्रश्न यह है कि क्या यही मंच विपक्षी दलों, नीतिगत खामियों, प्रशासनिक विफलताओं या जनसरोकारों से जुड़े असहज प्रश्नों के लिए भी उपलब्ध हो सकता है? सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो लोकतंत्र में किसी भी वैध राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, नागरिक मंच या जनहित समूह को अपने विचार रखने का अधिकार है। यदि कोई सरकार अपनी उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए भुगतान कर सकती है, तो विपक्ष या नागरिक संगठन भी तथ्यों और तर्कों के आधार पर सरकारी नीतियों की आलोचना या उनके दुष्परिणामों को उजागर करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का यही तकाजा है। लेकिन व्यवहारिक धरातल पर स्थिति इतनी सरल नहीं है। अधिकांश समाचार पत्रों की आर्थिक संरचना विज्ञापन आय पर निर्भर हो चुकी है। सरकारें देश की सबसे बड़ी विज्ञापनदाताओं में शामिल हैं। ऐसे में अनेक मीडिया संस्थान सत्ता से टकराव की स्थिति से बचना चाहते हैं। उन्हें आशंका रहती है कि यदि वे सरकार की आलोचना करने वाले प्रायोजित फीचर प्रकाशित करेंगे तो सरकारी विज्ञापन प्रभावित हो सकते हैं। यही कारण है कि सरकार समर्थक इम्पैक्ट फीचर तो सहजता से दिखाई देते हैं, लेकिन सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले भुगतान आधारित फीचर बहुत कम दिखाई देते हैं।

यहां एक महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न भी खड़ा होता है। क्या अखबारों का दायित्व केवल भुगतान लेने वाले पक्ष का संदेश पहुंचाना है, या उन्हें लोकतांत्रिक विमर्श के लिए समान अवसर भी उपलब्ध कराने चाहिए? यदि इम्पैक्ट फीचर केवल सत्ता की उपलब्धियों का मंच बन जाएं और आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए दरवाजे बंद कर दिए जाएं, तो यह लोकतांत्रिक संतुलन को कमजोर कर सकता है। लोकतंत्र केवल सरकार की बात सुनने का नाम नहीं है; यह सरकार से प्रश्न पूछने और वैकल्पिक दृष्टिकोणों को सामने लाने की व्यवस्था भी है।

हालांकि यह भी सच है कि विपक्ष द्वारा प्रायोजित फीचर और स्वतंत्र पत्रकारिता में अंतर बनाए रखना आवश्यक है। किसी भी आलोचनात्मक सामग्री को तथ्यों, आंकड़ों और प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए। यदि इम्पैक्ट फीचर केवल राजनीतिक प्रचार या दुष्प्रचार का माध्यम बन जाएं तो वे भी लोकतांत्रिक विमर्श को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए पारदर्शिता अनिवार्य है कि पाठक को स्पष्ट बताया जाए कि सामग्री प्रायोजित है। अब प्रश्न है–क्या भारतीय हिंदी अखबार ऐसा करने की हिम्मत दिखा सकते हैं? उत्तर एक शब्द में 'हाँ' या 'नहीं' नहीं है। कुछ अखबार और पत्रिकाएं आज भी सत्ता से असहज प्रश्न पूछने का साहस रखती हैं। वे खोजी रिपोर्टें प्रकाशित करते हैं और जनहित के मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन व्यापक परिदृश्य में आर्थिक दबाव, राजनीतिक ध्रुवीकरण, कॉर्पोरेट स्वामित्व और विज्ञापन निर्भरता ने मीडिया की स्वतंत्रता को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। ऐसे माहौल में सरकार की आलोचना करने वाले प्रायोजित इम्पैक्ट फीचर प्रकाशित करना कई संस्थानों के लिए जोखिम भरा निर्णय हो सकता है। फिर भी लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि मीडिया सत्ता और विपक्ष दोनों से समान दूरी बनाए रखे। यदि अखबार सरकार की उपलब्धियों के लिए इम्पैक्ट फीचर प्रकाशित करते हैं, तो उन्हें वैधानिक, तथ्यपरक और जिम्मेदार आलोचनात्मक दृष्टिकोणों के लिए भी स्थान देने का साहस दिखाना चाहिए। आखिर लोकतंत्र में सबसे बड़ा इम्पैक्ट किसी विज्ञापन का नहीं, बल्कि निर्भीक और संतुलित अभिव्यक्ति का होता है।

निष्कर्षतः, इम्पैक्ट फीचर केवल प्रशस्ति-पत्र नहीं बनने चाहिए। वे लोकतांत्रिक बहस का मंच भी बन सकते हैं, बशर्ते मीडिया संस्थान आर्थिक हितों से ऊपर उठकर अभिव्यक्ति की बहुलता और जनहित के सिद्धांत को महत्व दें। प्रश्न यह नहीं है कि विपक्ष ऐसा फीचर प्रकाशित करा सकता है या नहीं; वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में सभी पक्षों को समान अवसर देने का साहस दिखा पाएगा।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.-453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।
प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

कीड़ा-कांटा गठबंधन का उदय, अब देश चलेगा रेंगकर

व्यंग्य

प्रीतम लखवाल

लेखक व्यंग्यकार हैं।

भारतीय राजनीति ने अपने इतिहास में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। राजा-महाराजाओं से लेकर कॉरपोरेट और फिर सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (कोजपा) की अपार सफलता ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में अब सिर्फ 'वोटबैंक' की नहीं, बल्कि 'लोकल इन्फेक्शन' की ज़रूरत है। कॉकरोच पार्टी की इस अभूतपूर्व सफलता से प्रेरित होकर भारतीय राजनीतिक पटल पर अब एक और क्रांतिकारी 'घुन' लगने जा रहा है। 'दीमक जनता पार्टी' (दीजपा) का अभ्युदय बिल्कुल तय हो चुका है। सुगबुगाहट तो यहां तक है कि चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर सिर्फ दीमक ही नहीं, बल्कि चींटी, चींटा, केंचुआ और यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय पानी से बहकर आया एक ऑक्टोपस भी अपनी-अपनी पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म नंबर-10 लेकर कतार में खड़े हैं। 'दीमक जनता पार्टी' के राष्ट्रीय संयोजक (जो वर्तमान में एक पुरानी सरकारी फाइल के भीतर निवास कर रहे हैं) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया कि उनकी पार्टी का मुख्य एजेंडा 'सिस्टम की खोखलाहट को आधिकारिक मान्यता देना' है। 'हम कुछ नया नहीं करेंगे। जो काम इंसानी नेता सालों से धीरे-धीरे कर रहे थे, हम उसे जरा प्राकृतिक रूप से और तेज़ गति से करेंगे। हम व्यवस्था को अंदर से इतना खोखला कर देंगे कि वह खुद-ब-खुद गिर जाएगी और फिर हम उस पर अपनी नई कॉलोनी बसाएंगे। पार्टी का चुनावी सिंबल 'पुरानी अलमारी' रखने पर विचार किया जा रहा है। उनका नारा बेहद लोक-लुभावन है 'संसद हो या फाइलों का ढेर, हम बदलेंगे सबका फेट! चुनाव आयोग के मुख्य द्वार पर इस वक्त भारी गहमागहमी है। दरारों से घुसने की कोशिश कर रहे अन्य दलों का प्रोफाइल कुछ इस प्रकार है- ऑल इंडिया चींटी-चींटा महासंघ, इनका मानना है कि देश में इनसे बड़ा अनुशासित और कोई नहीं है। इनका चुनावी वादा है- 'चीनी के हर दाने पर पहला हक हमारा।' हालांकि, लाल चींटियों और काली चींटियों के बीच सीट-बंटवारे को लेकर अभी से 'काटा-काटी' शुरू हो गई है। भारतीय केंचुआ दल (भाकेद), ये ज़मीन से जुड़े हुए असली नेता हैं। इनका कहना है, 'रीढ़ की हड्डी न होना हमारी कमजोरी नहीं, हमारी यूएसपी है। बिना रीढ़ के किसी भी गठबंधन में फिट होना सबसे आसान होता है। ऑक्टोपस डेमोक्रेटिक फ्रंट, यह पार्टी वैश्विक स्तर पर गठबंधन के लिए बेताब है।

इनके पास आठ हाथ हैं, जिससे ये एक साथ आठ विभागों का भ्रष्टाचार संभाल सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी मांग है कि चुनावी रैलियों में 'मल्टी-टास्किंग' को अनिवार्य किया जाए। इस नए 'बायो-पॉलिटिक्स' युग के आने से पारंपरिक राजनेताओं के पसीने छूट रहे हैं। अब तक नेता जनता का खून चूसते थे, लेकिन अब मार्केट में 'मच्छर मोर्चा' भी आने को तैयार है, जो इस काम में पीएचडी धारक है। वहीं खटमल फ्रंट भी अपने दल के साथ कुर्सियों की संधियों में संधि की गुंजाइश सूंघ रहे हैं।

चुनाव विश्लेषकों का मानते हैं कि इन नए कीट-पतंगों वाले दलों के आने से रैलियों का खर्च बच जाएगा। कोई बड़ा स्टेज बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, एक गंदे नाले या पुरानी सीलन वाली दीवार पर ही पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक निपट जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव आयोग इन सबको हरी झंडी देगा तो देश का मतदाता किसे चुनेगा। वैसे भी, जनता पिछले कई दशकों से 'दीमकों' और 'कॉकरोचों' को ही चुनती आ रही है, बस इस बार फर्क सिर्फ इतना होगा कि उनके पास असली वाले कीड़े चुनने का 'ईमानदार' विकल्प मौजूद होगा!

सेहत

सत्य प्रकाश नायक

सामाजिक कार्यकर्ता एवं जेन्डर मुद्दों पर कार्यरत हैं

जागरूकता बढ़ी, भरोसा नहीं: मानसिक स्वास्थ्य की अधूरी लड़ाई

भारत के स्कूलों से आज केवल अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थी नहीं, बल्कि मानसिक रूप से मजबूत, आत्मविश्वासी और चुनौतियों का सामना करने वाले नागरिक तैयार करने की उम्मीद की जा रही है।

समस्या यह है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था लंबे समय तक पहले लक्ष्य के लिए बनी रही, दूसरे के लिए नहीं।

दशकों तक सफलता को अंकों, रैंक और परीक्षाओं के परिणामों से मापा गया। लेकिन 21वीं सदी की चुनौतियां केवल अकादमिक दक्षता से नहीं सुलझतीं। बदलती सामाजिक संरचनाएं, डिजिटल दुनिया का दबाव, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और भविष्य की अनिश्चितताएं ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रही हैं, जिनमें भावनात्मक मजबूती और मानसिक संतुलन पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं।

यह बदलाव नीतियों, कक्षाओं और सार्वजनिक विमर्श में स्पष्ट दिखाई देता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 केवल अकादमिक उपलब्धियों पर नहीं, बल्कि समग्र विकास पर जोर देती है। शिक्षा संस्थानों ने सोशल-इमोशनल लर्निंग (एसईएल), साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड (पीएफए) और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने जैसे प्रयासों को प्रोत्साहित किया है। राष्ट्रीय स्कूल मानसिक स्वास्थ्य नीति पर चर्चा भी तेज हुई है। शिक्षा के दायरे से आगे बढ़कर मानसिक स्वास्थ्य अब सार्वजनिक नीति का अहम विषय बन चुका है। टेली-मानस जैसी पहलें इसका उदाहरण हैं। हाल के वर्षों में भारत ने ब्रिक्स सहयोग के मंच पर भी मानसिक स्वास्थ्य को अधिक प्राथमिकता देने की वकालत की है।

लेकिन इन सकारात्मक पहलों के पीछे एक चिंताजनक सच्चाई भी मौजूद है।

आज के युवा भारतीय देश के इतिहास की सबसे अधिक शिक्षित पीढ़ियों में शामिल हैं। उनके पास जानकारी, तकनीक और अवसरों तक पहले से कहीं अधिक पहुंच है। इसके बावजूद शिक्षण समुदाय, माता-पिता, नियोक्ता और स्वास्थ्य विशेषज्ञ तनाव, चिंता, अकेलेपन, बर्नआउट और भावनात्मक परेशानियों से जुड़े मामलों में बढ़ोतरी की ओर लगातार ध्यान दिला रहे हैं। अब सवाल यह नहीं रह गया है कि मानसिक स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है या नहीं।

असल सवाल यह है कि क्या हमारी संस्थाएं इस चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं?

पिछले एक दशक में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सोच में बड़ा बदलाव आया है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 ने अधिकार-आधारित दृष्टिकोण को मजबूती दी और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दी। विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों ने सेवाओं का विस्तार किया, जबकि जागरूकता अभियानों ने मानसिक बीमारियों से जुड़े सामाजिक कलंक को कुछ हद तक कम करने में मदद की।

ये बदलाव आवश्यक थे।

लंबे समय तक मानसिक स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या उसकी अदृश्यता थी। लोग चुपचाप संघर्ष करते रहे क्योंकि भावनात्मक परेशानियों को अक्सर गलत समझा जाता था, नजरअंदाज किया जाता था या गंभीरता से नहीं लिया जाता था। इसलिए पहली चुनौती थीमानसिक स्वास्थ्य को सार्वजनिक चर्चा का विषय बनाना।

आज, हालांकि, एक नई चुनौती सामने आ रही है।

मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार यह रेखांकित कर रहे हैं कि जागरूकता अपने-आप लोगों को सहायता लेने के लिए प्रेरित नहीं करती। कोई व्यक्ति चिंता, अवसाद या बर्नआउट के लक्षण पहचान सकता है, फिर भी मदद लेने से बच सकता है। दुनिया भर के शोध बताते हैं कि सामाजिक कलंक, दूसरों की राय का डर, गोपनीयता को लेकर आशंकाएं और सामाजिक अपेक्षाएं लोगों को उपलब्ध सेवाओं तक पहुंचने से रोकती हैं।

यही अंतरजागरूकता और वास्तविक मदद लेने के बीच का अंतर मानसिक स्वास्थ्य नीति की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनता जा रहा है।

कार्यस्थलों का उदाहरण लें।

हालिया रिपोर्टों के अनुसार भारत में बर्नआउट की समस्या दुनिया के कई देशों की तुलना में अधिक गंभीर दिखाई देती है। दूसरी ओर, अनेक संस्थान अब काउंसलिंग सेवाएं, कर्मचारी सहायता कार्यक्रम और वेलनेस पहल चला रहे हैं। इसके बावजूद इन सेवाओं का उपयोग अपेक्षा से कम होता है। कई कार्यरत पेशेवरों को यह चिंता रहती है कि मानसिक स्वास्थ्य सहायता लेने पर सहकर्मी या प्रबंधन उन्हें किस नजर से देखेंगे। समस्या हमेशा सेवाओं की कमी नहीं होती। कई बार समस्या यह होती है कि लोगों को भरोसा नहीं होता कि सहायता लेने की कोई सामाजिक या पेशेवर कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी।

यही स्थिति युवाओं में भी दिखाई देती है।

भारत में हर वर्ष 13 हजार से अधिक विद्यार्थी आत्महत्या करते हैं। हर आंकड़े के पीछे एक अधूरी जिंदगी, एक बिखरता परिवार और एक अधूरा भविष्य छिपा होता है। परीक्षा का दबाव अक्सर इसकी प्रमुख वजह माना जाता है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि केवल परीक्षाओं को दोष देना समस्या को सीमित दृष्टि से देखना होगा।

दरअसल, यह केवल शिक्षा व्यवस्था का संकट नहीं है। यह उस सामाजिक माहौल पर भी गंभीर सवाल है, जिसमें हजारों युवा मदद मांगने से पहले हार मान लेते हैं। किशोरों और युवाओं की भावनात्मक परेशानियां सामाजिक तुलना, पारिवारिक अपेक्षाओं, भविष्य की अनिश्चितता, अकेलेपन, डिजिटल दबाव और सहायता लेने में झिझक जैसी अनेक वजहों से प्रभावित होती हैं।

शिक्षक-शिक्षिकाओं और शिक्षा विशेषज्ञों की एक

बड़ी चिंता यह है कि हमारे विद्यार्थी परीक्षाओं के लिए तो तैयार होते हैं, लेकिन असफलताओं का सामना करने के लिए नहीं।

एक किशोर या किशोरी कठिन गणितीय प्रश्न हल कर सकता या सकती है, लेकिन असफलता को स्वीकार करने में संघर्ष कर सकता या सकती है। कोई मेधावी विद्यार्थी पढ़ाई में उत्कृष्ट हो सकता है, फिर भी अपनी चिंता या भावनात्मक परेशानी के बारे में खुलकर बात करने में असहज महसूस कर सकता है। यह किसी व्यक्ति की कमजोरी नहीं है। यह उस शिक्षा व्यवस्था की सीमा है जिसने लंबे समय तक उपलब्धियों को भावनात्मक क्षमताओं से अधिक महत्व दिया।

यही कारण है कि सोशल-इमोशनल लर्निंग (एसईएल) को दुनिया भर में तेजी से महत्व मिल रहा है। एसईएल भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने, सहानुभूति विकसित करने, संवाद कौशल को मजबूत बनाने, स्वस्थ संबंध स्थापित करने, जिम्मेदार निर्णय लेने और चुनौतियों से उबरने जैसी क्षमताओं पर जोर देता है। इन्हें अक्सर 'सॉफ्ट स्किल्स' कहा जाता है, लेकिन शोध बताते हैं कि इनका प्रभाव केवल मानसिक स्वास्थ्य पर ही नहीं, बल्कि सीखने की क्षमता, कक्षा में सहभागिता और दीर्घकालिक विकास पर भी पड़ता है।

इस दृष्टि से देखें तो एनईपी में समग्र विकास पर दिया गया जोर केवल पाठ्यक्रम सुधार नहीं है। यह शिक्षा को केवल परीक्षा परिणामों के आधार पर आंकने की सोच से आगे बढ़ने का प्रयास है। इसी तरह साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता को मजबूत करने की पहलें यह स्वीकार करती हैं कि भावनात्मक स्वास्थ्य कोई अतिरिक्त विषय नहीं, बल्कि शिक्षा का अभिन्न हिस्सा है।

इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं कि स्कूल मानसिक स्वास्थ्य क्लीनिक बन जाएं।

भारत पहले से ही मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कमी से जूझ रहा है और विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। लेकिन कोई भी देश केवल तब उपचार देकर मजबूत मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं बना सकता, जब समस्याएं गंभीर रूप ले चुकी हों। फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों के अनुभव बताते हैं कि रोकथाम, शुरुआती हस्तक्षेप और सहयोगी वातावरण प्रभावी मानसिक स्वास्थ्य रणनीति के महत्वपूर्ण आधार हैं।

यहीं पर शिक्षक-शिक्षिकाओं की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। अक्सर वही सबसे पहले विद्यार्थियों के व्यवहार में बदलाव, अलगाव, सहभागिता में कमी या मानसिक तनाव के संकेत पहचानते हैं। साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड शिक्षकों को मनोचिकित्सक नहीं बनाता, बल्कि उन्हें यह समझने में सक्षम बनाता है कि समस्या को कैसे पहचानें, प्रारंभिक सहयोग कैसे दें और जरूरत पड़ने पर विद्यार्थी को उचित सहायता तक कैसे पहुंचाएं।

इन पहलों का महत्व केवल स्कूलों तक सीमित नहीं है। दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य को अब केवल स्वास्थ्य का नहीं, बल्कि विकास का मुद्दा माना जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कई बार यह रेखांकित कर चुका है कि मानसिक स्वास्थ्य का शिक्षा, उत्पादकता और सामाजिक भागीदारी से गहरा संबंध है। अर्थशास्त्री भी अब यह समझने लगे हैं कि अनुपचारित मानसिक समस्याओं की कीमत केवल व्यक्ति नहीं, पूरा समाज चुकाता है।

ऐसे देश के लिए जो आर्थिक विकास और जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाना चाहता है, मानव संसाधन को केवल तकनीकी कौशल तक सीमित नहीं किया जा सकता। नवाचार, उत्पादकता, अनुकूलन क्षमता और सामाजिक एकजुटताइन सभी की नींव कहीं न कहीं मानसिक स्वास्थ्य पर टिकी होती है।

मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा में एक और महत्वपूर्ण पक्ष अक्सर पर्याप्त ध्यान नहीं पाता परिवार।

भारत में अधिकांश युवा सबसे पहले किसी विशेषज्ञ के पास नहीं, बल्कि अपने घर और परिवार की ओर देखते हैं। यदि भावनात्मक संघर्षों को कमजोरी, बहाना या अनुशासनहीनता मान लिया जाए, तो सबसे अच्छी नीतियां भी सीमित प्रभाव ही छोड़ पाएंगी। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील समाज की शुरुआत अक्सर किसी अस्पताल या काउंसलिंग सेंटर से नहीं, बल्कि घर के भीतर होने वाली बातचीत से होती है।

शायद यही वजह है कि मानसिक स्वास्थ्य धीरे-धीरे सार्वजनिक नीति के केंद्र की ओर बढ़ रहा है।

लेकिन केवल नीतियां पर्याप्त नहीं हैं।

काउंसलिंग सेवाएं महत्वपूर्ण हैं। काउंसलर महत्वपूर्ण हैं। नीतियां और कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण हैं।

लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की असली परीक्षा वहां होती है, जहां कोई व्यक्ति पहली बार मदद मांगने का निर्णय लेता है।

उस कक्षा में, जहां असफलता को जीवन की हार नहीं माना जाता। उस कार्यस्थल पर, जहां मानसिक तनाव स्वीकार करना पेशेवर जोखिम न बन जाए।

और उस परिवार में, जहां भावनात्मक संघर्षों पर चुप्पी नहीं, संवाद हो। पिछले एक दशक में भारत ने मानसिक स्वास्थ्य को हाशिये से निकालकर राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र तक पहुंचाया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन जागरूकता बढ़ाना केवल पहला कदम था। असली चुनौती अब शुरू होती हैऐसी संस्थाएं और ऐसा सामाजिक वातावरण तैयार करना, जहां मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और साहस का प्रतीक माना जाए। क्योंकि किसी भी समाज का भविष्य केवल इस बात से तय नहीं होता कि उसके युवा कितने शिक्षित हैं, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि वे संकट के समय कितने सुरक्षित, समर्थ और सुने हुए महसूस करते हैं। भारत की मानसिक स्वास्थ्य नीति की सफलता का आकलन घोषणाओं, अभियानों या बजट के आंकड़ों से नहीं होगा। उसकी असली कसौटी यह होगी कि क्या कोई विद्यार्थी, शिक्षक-शिक्षिका, कार्यरत पेशेवर या अभिभावक टूटने से पहले मदद मांग पाने में सहज महसूस करता है।

यदि भारत यह भरोसा पैदा कर पाया, तो यह केवल मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार नहीं होगा। यह एक ऐसे समाज की नींव होगी जो उपलब्धियों के साथ-साथ मानवीय गरिमा को भी महत्व देता है।

क्योंकि किसी राष्ट्र की वास्तविक ताकत उसके सबसे सफल लोगों से नहीं, बल्कि उसके सबसे संघर्षरत लोगों के लिए बनाए गए सहारे से मापी जाती है।

विश्व साइकिल दिवस पर विशेष

कुमार सिद्धार्थ

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।

जीवन के लिए जरूरी साइकल का साथ

हर वर्ष 3 जून को 'विश्व साइकिल दिवस' मनाया जाता है। 'संयुक्त राष्ट्र संघ' ने इस दिवस को इसलिए मान्यता दी ताकि दुनिया को यह याद दिलाया जा सके कि साइकिल केवल दोपहियों वाला साधारण वाहन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक बचत और टिकाऊ विकास का प्रभावी साधन है। आज जब दुनिया पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों, ऊर्जा संकट, प्रदूषण, और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रही है, तब साइकिल फिर से चर्चा के केंद्र में आ गई है।

एक समय था, जब साइकिल भारत ही नहीं, दुनिया के अनेक देशों में आम आदमी के जीवन का अभिन्न हिस्सा थी। आधुनिकता की दौड़ में मोटर वाहनों की चमक-दमक के बीच साइकिल धीरे-धीरे सड़कों से हाशिये पर चली गई। अब दुनिया फिर समझ रही है कि विकास का अर्थ केवल तेज रफ्तार वाहन नहीं, बल्कि ऐसे साधन भी हैं, जो टिकाऊ हों और समाज के लिए लाभकारी हों।

आज जब पर्यावरण संरक्षण और 'ग्रीन मोबिलिटी' की बात होती है, तो इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी तकनीक, चार्जिंग स्टेशन और नई परिवहन योजनाओं की खूब चर्चा होती है। सरकारें इलेक्ट्रिक कारों और दो पहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बना रही हैं। शहरों में चार्जिंग प्वाइंट स्थापित किए जा रहे हैं, लेकिन अफसोस है कि इन चर्चाओं के बीच पर्यावरण-अनुकूल साधन, पारंपरिक 'साइकिल' अक्सर गायब हो जाती है।

साइकिल ऐसा वाहन है, जिसे न पेट्रोल चाहिए, न डीजल, न बैटरी और न ही कोई चार्जिंग-स्टेशन। यह पूरी तरह मानव ऊर्जा पर आधारित है। इसके बावजूद शहरी परिवहन योजनाओं में इसे वह प्राथमिकता नहीं मिलती, जिसकी यह हकदार है। कई शहरों में 'साइकिल लेन' की योजनाएं बनीं, लेकिन अनेक जगहों पर वे अतिक्रमण, खराब डिजाइन और उपेक्षा के कारण सफल नहीं हो सकीं।

साइकिल केवल परिवहन का साधन नहीं, बल्कि एक समय सामाजिक समानता और सादगी का प्रतीक भी रही है। एक दौर में शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, किसान और छोटे अधिकारी सभी साइकिल से यात्रा करते थे। इसमें वर्ग भेद कम दिखाई देता था। यही कारण है कि कई विचारकों ने साइकिल को लोकतांत्रिक वाहन कहा।

वर्ष 1960 के बाद जैसे-जैसे मोटर वाहनों की संख्या बढ़ी, साइकिल पीछे छूटने लगी। कारें और बड़े वाहन आधुनिकता और उपभोक्तावाद के प्रतीक बन गए। धीरे-धीरे साइकिल को पिछड़ेपन से जोड़कर देखा जाने लगा। परिणाम यह हुआ कि सड़कों पर कारों का कब्जा बढ़ता गया और साइकिल हाशिये पर चली गई। आज फिर परिस्थितियां बदल रही हैं। दुनिया समझ रही है कि महंगे ईंधन, बढ़ते प्रदूषण और जलवायु संकट के दौर में साइकिल पिछड़ेपन का नहीं, बल्कि समझदारी और टिकाऊ जीवन शैली का प्रतीक है।

भारत आज भी दुनिया के बड़े साइकिल उपयोग करने वाले देशों में शामिल है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार देश में दस से 12 करोड़ से अधिक परिवारों के पास साइकिल उपलब्ध है। ग्रामीण भारत में इसका उपयोग और भी अधिक है। साइकिल उद्योग के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल एक करोड़ से अधिक नई साइकिलों की बिक्री होती है। पंजाब का लुधियाना देश के साइकिल निर्माण का बड़ा केंद्र माना जाता है। भारत दुनिया के बड़े साइकिल उत्पादक देशों में भी शामिल है।

दुनियाभर में साइकिल की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व में एक अरब से अधिक साइकिलें उपयोग में हैं। यूरोप, चीन, जापान और एशिया के कई देशों में साइकिल रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। कई देशों में लाखों लोग प्रतिदिन साइकिल से अपने कार्यस्थल पहुंचते हैं। भारत में भी साइकिल प्रेमियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब साइकिल केवल ग्रामीण या गरीब का वाहन नहीं रही, बल्कि शहरों में भी आर्थिक रूप से सम्पन्न युवा, पेशेवर, फिटनेस प्रेमी और पर्यावरण के प्रति जागरूक लोग इसे अपना रहे हैं।

आज दुनिया ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रही है। अंतरराष्ट्रीय तनाव, युद्ध और आपूर्ति बाधाओं का असर सीधे पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता और कीमतों पर पड़ता है। भारत जैसे देशों में, जहां बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद आयात किए जाते हैं, इसका असर आम आदमी की जेब पर साफ दिखाई देता है। इनकी कीमतें बढ़ने से न केवल यात्रा महंगी होती है, बल्कि परिवहन लागत बढ़ने से महंगाई भी बढ़ती है। ऐसे में साइकिल एक विकल्प है, जो पूरी तरह ईंधन मुक्त है।

छोटी दूरी के लिए अगर लोग साइकिल अपनाएं, तो ईंधन की खपत कम होगी, घरेलू खर्च घटेगा। यही कारण है कि ऊर्जा संकट के दौर में साइकिल फिर 'भविष्य के परिवहन' के रूप में देखी जा रही है। देश-दुनिया में कई नेता, अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता साइकिल से आने-जाने या सार्वजनिक साइकिल अभियानों में भाग लेने का संदेश देते रहे हैं। यह केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि एक संकेत है कि सुविधा और जिम्मेदारी के बीच संतुलन संभव है।

आज दुनिया का सबसे बड़ा संकट जलवायु परिवर्तन है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें छोड़ते हैं, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है और धरती का तापमान बढ़ता है। साइकिल इस समस्या का सबसे सरल समाधान है। यह न धुआं छोड़ती है, न शोर करती है और न ही सड़क पर अधिक जगह घेरती है। शहरों में अगर छोटी दूरी के लिए साइकिल उपयोग को बढ़ावा मिले, तो प्रदूषण और ट्रैफिक दोनों कम हो सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया के कई शहरों में अलग 'साइकिल लेन,' सार्वजनिक साइकिल सेवा और सुरक्षित ट्रैक बनाए जा रहे हैं।

साइकिल चलाना केवल सफर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का भी साथी है। यह हृदय को मजबूत बनाती है, वजन नियंत्रित रखती है, मांसपेशियों को सक्रिय करती है और मानसिक तनाव कम करती है। पर्यावरण-अनुकूल परिवहन की चर्चा में अगर साइकिल को फिर केंद्र में लाया जाए, सुरक्षित 'साइकिल लेन' बनाई जाएं और लोगों को इसे अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए, तो यह न केवल आम आदमी के लिए राहत होगी, बल्कि देश और दुनिया के लिए भी बड़ा समाधान साबित हो सकती है। सच तो यह है कि साइकिल केवल अतीत की याद नहीं, बल्कि वर्तमान की जरूरत और भविष्य की दिशा बनकर फिर हमारे सामने खड़ी है। दो पहियों पर चलने वाली यह साधारण सवारी हमें एक स्वस्थ, सस्ता, स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जा सकती है। (सप्रेस)

मुद्दा

महिम दुबे

लेखक एनएलयू दिल्ली से विधि स्नातक हैं और न्यायिक सेवा के अभ्यर्थी रह चुके हैं।

कॉकरोच, आकांक्षाएँ और न्यायिक सेवा प्रवेश परीक्षाएँ

न्यायिक सेवा प्रवेश परीक्षा प्रणाली, जो अनियमितताओं से भरी हुई है, लगातार ऐसे युवाओं को पैदा कर रही है जिन्हें आज सार्वजनिक विमर्श में 'कॉकरोच' कहा जाने लगा है – ऐसे बेरोज़गार स्नातक जो तैयारी और देरी के अंतहीन चक्र में फँसे हुए हैं। लेकिन त्रासदी यह नहीं है कि इस व्यवस्था में 'कॉकरोच' मौजूद हैं; असली त्रासदी यह है कि इस व्यवस्था ने ऐसा वातावरण बना दिया है जहाँ केवल जीवित रह पाना ही किसी संक्रमण जैसा प्रतीत होता है।

न्यायिक सेवा प्रवेश परीक्षा प्रणाली एक ऐसे वर्ग को पैदा करने की उपजाऊ भूमि बन गई है जिसे हाल के सार्वजनिक विमर्श में 'कॉकरोच' कहा गया है। मनमाने ढंग से आयोजित की जाने वाली ये परीक्षाएँ अनेक खामियों से ग्रस्त हैं, जैसे– त्रुटिपूर्ण उत्तर कुंजियाँ, अनिश्चित समय-सीमाएँ, और बेरोज़गार अभ्यर्थियों के भविष्य के प्रति पूर्ण उदासीनता।

हाल की न्यायिक सेवा परीक्षाएँ दर्शाती हैं कि ये कमियाँ किस हद तक व्यवस्था में जड़ जमा चुकी हैं। झारखंड न्यायिक सेवा प्रवेश परीक्षा, 2023 इसका एक प्रमुख उदाहरण है। झारखंड की निचली न्यायपालिका के लिए यह परीक्षा 2023 में अधिसूचित की गई थी, परंतु 2024 में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अब तक लंबित है। इसका कारण गलत उत्तर-कुंजी को लेकर मुकदमेबाजी और प्रशासनिक शिथिलता है।

परीक्षा चक्र पूरा होने में देरी के अलावा, लगातार परीक्षा चक्रों के बीच कई वर्षों का मनमाना अंतराल भी एक गंभीर समस्या है। उदाहरण के लिए, 2022 के बाद से उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के लिए कोई नई रिक्ति घोषित नहीं की गई है। ये घटनाएँ केवल प्रशासनिक अनियमितताएँ नहीं हैं, बल्कि भारत की न्यायिक प्रणाली में व्याप्त गहरे संकट के लक्षण हैं।

मलिक मजहर सुल्तान – वह निर्णय जिसने कुछ नहीं बदला

मलिक मजहर सुल्तान बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने अभ्यर्थियों की पीड़ा को स्वीकार करते हुए कहा था कि परीक्षाओं में देरी से बचना चाहिए क्योंकि यह 'अभ्यर्थियों में धीरे-धीरे बढ़ती निराशा' का कारण बनती है।

न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह निश्चित समय-सारणी और संरचित समय-सीमाएँ तय करें। दुर्भाग्यवश, आज तक इस निर्णय का पालन नहीं हुआ।

विडंबना यह है कि जब भी नीट जैसी किसी परीक्षा को पेपर लीक या अन्य कारणों से चुनौती दी जाती है, तब यह मांग उठती है कि परीक्षा न्यायालय की निगरानी में कराई जाए, क्योंकि आम जनता को विश्वास है कि न्यायालय की निगरानी में कोई त्रुटि नहीं

होगी। न्यायालय सबकी रक्षा करते हैं और उन्हें करनी भी चाहिए; फिर भी अपनी ही व्यवस्था से पीड़ित अभ्यर्थियों की दुर्दशा अब तक अनदेखी है।

मूल समस्या: अधीनता की संस्कृति

परीक्षा संबंधी अधिकांश समस्याओं की जड़ भारतीय न्यायपालिका में व्याप्त अधीनता की संस्कृति है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ ने स्वयं एक भाषण में कहा था कि जहाँ सिविल सेवाओं में युवा अधिकारियों को सहकर्मी की तरह देखा जाता है, वहीं न्यायिक व्यवस्था में युवा न्यायाधीशों को अधीनस्थ स्थिति में रखा जाता है। इससे व्यवस्था उनके सुझावों और अनुभवों से लाभ उठाने का अवसर खो देती है।

यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्भय सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में चिंता व्यक्त की थी कि अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अनुशासनात्मक कार्रवाई के भय से जमानत देने में भी हिचकते हैं।

इस अधीनस्थ संस्कृति में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश–जो प्रायः सीधे बार से नियुक्त होते हैं– जिला न्यायालय के न्यायाधीशों से अपेक्षाकृत उच्च स्थिति में होते हैं। परिणामस्वरूप, इस अत्यधिक पदानुक्रमित व्यवस्था के सबसे निचले स्तर पर खड़े अभ्यर्थियों की पीड़ा अनदेखी रह जाती है।

'कॉकरोच अभ्यर्थी' का निर्माण

विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के 2020 के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि इलाहाबाद, बॉम्बे, केरल, मद्रास और पटना उच्च न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ताओं में से 46 प्रतिशत युवा प्रथम-पीढ़ी के वकील अपने शुरुआती दो वर्षों में रू. 5000 प्रतिमाह से भी कम कमाते हैं। यह राशि अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन से भी कम है। सिर्फ वकालत ही नहीं, कॉर्पोरेट कानून क्षेत्र भी हर स्नातक के लिए सुलभ नहीं है। लॉ मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, हर वर्ष एक लाख विधि स्नातकों में से केवल 400-600 ही देश की शीर्ष लॉ फर्मों में नौकरी पा पाते हैं। जब अवसर इतने सीमित हों, तब देश का युवा अपनी जवानी एक ऐसी परीक्षा की तैयारी में खपा देता है जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी होने के साथ-साथ पूरी तरह अनिश्चित भी है। इनमें से कई असफल हो जाते हैं, और कई मुकदमेबाजी के कारण परिणाम देखने का अवसर भी नहीं पा पाते। इस प्रकार वे केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं – लगभग एक कॉकरोच की तरह।

निष्कर्ष

'कॉकरोच' का यह रूपक केवल इसलिए चिंताजनक नहीं है कि यह अमानवीय शब्द है, बल्कि इसलिए भी कि यह उन हजारों बेरोज़गार युवाओं की वास्तविक स्थिति को उजागर करता है, जो पेपर लीक, देरी और अनिश्चितताओं से ग्रस्त परीक्षाओं की तैयारी में फँसे हुए हैं। यह केवल परीक्षा प्रणाली की विफलता नहीं, बल्कि उस व्यवस्था की नैतिक विफलता है जो अपने ही भविष्य के न्यायाधीशों के साथ न्याय नहीं कर पा रही।

जल गंगा संवर्धन अभियान से गांव-गांव पहुंचेगा भरपूर पानी : सीएम डॉ. यादव

भोपाल। वीर भारत न्यास द्वारा आयोजित सदानीरा समागम में सोमवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में जल का विशेष महत्व है और जल के बिना कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण नहीं माना जाता। उन्होंने रहीम के प्रसिद्ध दोहे का उल्लेख करते हुए कहा कि पानी केवल जीवन का आधार नहीं बल्कि संस्कृति और सभ्यता का भी मूल तत्व है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में जल संरक्षण के लिए व्यापक अभियान चल रहे हैं और इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग दो लाख जल संरचनाओं पर कार्य किया जा चुका है, जबकि बड़ी संख्या में अन्य परियोजनाओं पर काम जारी है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने सदानीरा समागम

के सफल आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई दी।

इस अवसर पर वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने मुख्यमंत्री का स्मृति चिन्ह एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों जगन्नाथ सामी उच्चायुक्त फिजी गणराज्य, इवागोरास वराईओ नाइडेस उच्चायुक्त सायप्रस, सुश्री वनेसा एडरियाने,कल्चर हेड मैक्सीको दूतावास के साथ माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल राज्यमंत्री लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी, भूजल बोर्ड भारत सरकार से अशोक विश्वाल उपस्थित थे।

आरंभ में स्वागत भाषण देते हुए वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश आज जल संरक्षण के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। भारत भवन में आयोजित सात दिवसीय सदानीरा समागम में विभिन्न देशों के राजनयिकों, पर्यावरण विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, साहित्यकारों और कलाकारों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में पंचमहाभूतों एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर सार्थक संवाद हुए, जिनका दस्तावेजीकरण किया जा रहा है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, वीर भारत न्यास और इसरो के सहयोग से तैयार किए गए भूजल एटलस अन्तर्जली यात्रा भोपाल, इंदौर, ग्वालियर का भी अनावरण किया।

धार में युवा संगम - रोजगार मेले का भव्य आयोजन

15 नामी कंपनियां आईं ,सैकड़ों युवाओं के चेहरे खिल उठे

रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार, अप्रेंटिसशिप, करियर काउंसलिंग और रक्तदान शिविर का हुआ संगम

राजेश शर्मा, धार। ऐतिहासिक राजा भोज की नगरी ने 1 जून को नई इबारत लिखी। अवसर था 'युवा संगम' का। जहां युवाओं को एक ही जगह पर रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार, अप्रेंटिसशिप, करियर काउंसलिंग का अवसर मिला। इस 'युवा संगम' में कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने भाग ले कर ना केवल युवाओं को मार्गदर्शन दिया बल्कि हाथों हाथ उन्हें रोजगार के अवसर भी प्रदान किए। सैकड़ों युवाओं के चेहरों पर मुस्कान थी। 'युवा संगम' फेयर की इस अनूठी पहल के लिए युवाओं ने पीएम मोदी जी , सीएम डॉ. मोहन यादव जी और जिला प्रशासन, जिला रोजगार कार्यालय धार, आईटीआई धार और कॉर्पोरेट जगत की कंपनियों के प्रति आभार व्यक्त किया। 'युवा संगम' फेयर की इस अनूठी पहल में रोजगार मेला, स्वरोजगार मेला, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना एवं मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के तहत युवाओं को एक ही छत के नीचे कई अवसर उपलब्ध कराए । करियर काउंसलर और एक्सपर्ट ने युवाओं को करियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल टिप्स दी जिससे यूथ को अपना भविष्य संवारने में मदद मिलेंगी।

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा रोजगार संचालनालय, भोपाल के निर्देश पर धार जिले में युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जिला प्रशासन, कौशल विकास और रोजगार विभाग तथा जिला रोजगार कार्यालय, धार द्वारा 'मध्य प्रदेश डे-राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन' के संयुक्त तत्वाधान में शासकीय आईटीआई कॉलेज में 'युवा संगम' कार्यक्रम आयोजित किया गया।

15 कंपनियों ने किया 124 युवाओं का प्राथमिक चयन

जिला रोजगार अधिकारी राहुल मंडलोई ने बताया कि इस रोजगार मेले में 167 बालक-बालिकाओं ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से अपना पंजीयन कराया था। मेले में सम्मिलित हुई 15 प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा निर्धारित मापदंडों और कड़े साक्षात्कार (इंटरव्यू) के उपरांत कुल 124 आवेदकों का प्राथमिक रूप से चयन किया गया। इनमें से 122 आवेदकों को रोजगार हेतु तथा 2 आवेदकों को अप्रेंटिसशिप हेतु चुना गया है। जिला रोजगार अधिकारी ने सभी चयनित युवाओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रशिक्षण अधिकारी अनिल कुमार राजौरिया, प्रवीण सावले , टीपीओ जितेंद्र बदनौरा ने भी बहुमूल्य योगदान दिया।

9.50 लाख का ऋण स्वीकृत, करियर काउंसलिंग से संवरा भविष्य

युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से मेले में शासन की विभिन्न लोन योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 1 हितग्राही को 9 लाख 50 हजार रुपये का ऋण स्वीकृति पत्र मौके पर ही वितरित किया गया। युवाओं के सही मार्गदर्शन के लिए करियर काउंसलिंग सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें 85 बच्चों को करियर मार्गदर्शन दिया गया तथा 58 बच्चों की वन-टू-वन काउंसलिंग की गई। मोटिवेशनल स्पीकर राजेश शर्मा ने युवाओं को बहुमूल्य मोटिवेशनल टिप्स देते हुए कार्यक्रम का संचालन किया।

10 यूनिट रक्तदान, आईटीआई को मिला प्रशस्ति पत्र

युवा संगम कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में शासकीय आईटीआई धार के जागरूक छात्रों और स्टाफ सदस्यों द्वारा उत्साहपूर्वक 10 यूनिट रक्तदान किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा आईटीआई संस्था के इस मानवीय प्रयास के लिए उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के सफल आयोजन पर शासकीय आईटीआई के स्टाफ तथा जिला रोजगार कार्यालय के भगवान गोयल द्वारा सभी आगंतुकों, नियोक्ताओं और सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

मांडू में पर्यटन को पंख लगाने की कवायद

होटल व्यापारियों ने सीएम मोहन यादव से की मुलाकात, नर्मदा लाइन और सुरक्षा की रखी मांग

धार। ऐतिहासिक पर्यटन नगरी मांडू में सुविधाओं के विस्तार और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थानीय होटल व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। धरमपुरी विधायक कालू

सिंह ठाकुर के नेतृत्व और होटल व्यवसायी योगेश अग्रवाल की अगुवाई में पहुंचे व्यापारियों ने मांडू की समस्याओं से सीएम को अवगत कराया।

सुविधाएं बढ़ेंगी तो बढ़ेगा पर्यटन

अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि मांडू विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, लेकिन यहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव व्यवसाय के साथ-साथ पर्यटकों के लिए भी चिंता का विषय है। व्यापारियों ने प्रमुखता से मांडू में पेयजल की किल्लत का मुद्दा उठाया और नर्मदा जल प्रदाय योजना को जल्द शुरू करने की मांग की, ताकि होटल और पर्यटकों को निर्बाध पानी मिल सके। इसके साथ ही, होटल क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने और पर्यटकों की सुविधा के लिए अन्य बुनियादी ढांचे विकसित करने का आग्रह किया।

सीएम ने दिया सकारात्मक आश्वासन

व्यापारियों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि यदि मांडू में सुविधाओं का विस्तार होता है, तो निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, जिसका लाभ स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने व्यापारियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मांडू के विकास और यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम ने समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देने की बात कही। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रूप से कुलदीप सिंह बुंदेला, मिलन बोड़ाने सहित अन्य होटल व्यवसायी उपस्थित रहे।

कांग्रेसियों को एकजुट कर जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत करना प्रमुख लक्ष्य : अजय सिंह

बूथ स्तर का सामंजस्य ही संगठन की असली ताकत : निलय डागा

बैतूल। कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका देने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से मंगलवार को जिला कांग्रेस कार्यालय बैतूल में कांग्रेस की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मंत्री, चुरहट के विधायक अजय सिंह (राहुल भैया) ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेसियों को एकजुट कर गांव, वार्ड और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना ही पार्टी का प्रमुख लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि है और कांग्रेस की वास्तविक ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता ही हैं। अजय सिंह राहुल भैया ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस को जनता के बीच और अधिक सक्रियता के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि संगठन तभी मजबूत होगा जब हर कार्यकर्ता को सम्मान और जिम्मेदारी मिलेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाने और कांग्रेस की नीतियों को घर-घर तक

पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। बैतूल प्रवास के दौरान अजय सिंह (राहुल भैया) सबसे पहले जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा के निवास पहुंचे। यहां उनके साथ सुखदेव पांसे, समीर खान, ब्रजभूषण पांडे, मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रकोष्ठ एवं विभाग के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेन्द्र सिंह चौहान, लोकेश पगारिया, लवलेश बब्बा राठौर, मोनू बड़ोनिया और जितेन्द्र इवने उपस्थित रहे। स्वल्पाहार के दौरान संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की गई।

वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई रणनीतिक चर्चा..- इसके बाद अजय सिंह, पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे के बैतूल स्थित निवास पहुंचे, जहां निलय डागा, अनुराग मिश्रा, मनोज मालवे, नवनीत मालवीय, हेमंत वागद्रे, हेमंत पगारिया, नरेन्द्र मिश्रा सहित वरिष्ठ नेताओं के साथ चाय पर चर्चा हुई। इस दौरान संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं की भूमिका और जनसंपर्क गतिविधियों को लेकर विचार-विमर्श किया गया। चाय पर चर्चा के बाद अजय सिंह राहुल भैया सीधे कांग्रेस कार्यालय बैतूल गंज पहुंचे, जहां उन्होंने जिलेभर से आए कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम का संचालन जिला संगठन महामंत्री ब्रजभूषण पांडे ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन कांग्रेस प्रवक्ता लवलेश बब्बा राठौर ने किया।

बूथ स्तर का सामंजस्य ही सफलता की कुंजी...

जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय डागा ने इस अवसर पर कहा कि बूथ स्तर तक सामंजस्य और मजबूत संगठन ही कांग्रेस की असली ताकत है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी और बेहतर समन्वय के माध्यम से संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी और कांग्रेस को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूती प्रदान होगी। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सुखदेव पांसे ने कहा कि कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक भाजपा की जनविरोधी नीतियों का विरोध करती रहेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच लगातार संवाद बनाए रखने, उनकी समस्याओं को समझने और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संघर्ष जनता के अधिकारों और विकास के मुद्दों के लिए लगातार जारी रहेगा। इस बैठक में प्रमुख अतिथियों के अलावा प्रदेश सचिव समीर खान, पूर्व विधायकद्वय ब्रम्हा भलावी, धरमूसिंह सिरसाम, डॉ.पी.आर.बोडखे, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र जैसवाल, अध्यक्ष महिला कांग्रेस श्रीमित पुष्पा पेद्राम, नितिन मेहतो, देवेंद्र मोनू वाघ सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे।

मलेरिया जागरूकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर मलेरिया निरोधक माह का किया शुभारंभ

बैतूल। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1 जून को मलेरिया निरोधक माह का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज कुमार हुरमाडे द्वारा मलेरिया जागरूकता रथ को कार्यालय परिसर से हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। यह जागरूकता रथ जिले में विभिन्न विकासखंडों के चयनित ग्रामों में भ्रमण करेगा।

एक जून से 30 जून तक मलेरिया निरोधक माह के दौरान यह जागरूकता रथ ग्रामों में जाकर लोगों को मलेरिया से बचाव के प्रति सचेत करेगा। रथ द्वारा मलेरिया जागरूकता माह के दौरान मलेरिया से बचाव के साधनों से भली भांति अवगत कराया जाएगा, साथ ही मच्छरदानी के उपयोग के लिये लोगों को प्रेरित किया जाएगा। जागरूकता रथ में बुखार रोगियों के रक्त के नमूने लेकर जांच एवं मलेरिया पाए जाने पर उपचार की पूर्ण सुविधा उपलब्ध है। मलेरिया जनजागरण रथ को रवाना करने के उपरांत जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सीएमएचओ डॉ मनोज हुरमाड़े ने बताया कि पूर्व वर्षो में मलेरिया के केसो की संख्या बहुत ज्यादा होती थी, वर्तमान में यह संख्या न्यूनतम है, स्वास्थ्य विभाग एवं जनसहयोग से मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में भारी सफलता मिली है। मलेरिया रथ हर ब्लाक में जाकर जागरूकता संदेश देगा। उन्होंने बताया कि वर्षाकाल प्रारंभ होने के साथ-साथ मच्छरों की संख्या बढ़ने लगती है, जगह-जगह पानी इकठ्ठा होने से मच्चरों की बहुतायत संख्या हो जाती है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर जनमानस को संदेश देंगे कि मलेरिया से बचाव के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाए।

राहुल भैया को दिया स्मृति चिन्ह

सोहागपुर। वाटिका ग्रार्डन में संवाद एवं कार्यकर्ता सम्मेलन में अजय सिंह राहुल भैया का कार्यकताओं ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। स्मृति चिन्ह नगर में स्थापित शिव पार्वती की पाषाण प्रतिमा का प्रदान किया गया। इस अवसर कांग्रेस जन उपस्थित थे।

सोहागपुर। सोहागपुर आगमन के पूर्व प्रदेश के वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल भैया ने नगर के समीपवर्ती ग्राम करनपुर में नवनिर्मित रूपेश्वर शिव मंदिर में पूजा-अर्चना की ।

केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने राष्ट्रीय संत साध्वी ऋतम्भरा जी से वृंदावन में की भेंट, भोजशाला दर्शन हेतु किया आमंत्रित

धार। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री एवं धार लोकसभा सांसद सावित्री ठाकुर ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर वृंदावन पहुंचकर विख्यात राष्ट्रीय संत एवं वात्सल्य ग्राम की संस्थापिका पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतम्भरा जी से शिष्टाचार भेंट की तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर श्रीमती ठाकुर ने कहा कि पूज्य दीदी माँ का सान्निध्य सदैव आध्यात्मिक ऊर्जा, राष्ट्रभावना एवं सेवा के संस्कारों से ओतप्रोत रहता है।

सीएमओ के औचक निरीक्षण में अनुपस्थित मिले कर्मचारी, वेतन काटने के निर्देश

बैतूल। नगर पालिका में कार्यालयीन अनुशासन को लेकर सीएमओ नवनीत पाण्डेय ने मंगलवार को सख्त रुख अपनाते हुए विभिन्न शाखाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की उपस्थिति, कार्य व्यवस्था एवं कार्यालय संचालन की स्थिति का गहन परीक्षण किया गया। जांच के दौरान कुछ कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित पाए गए, जिस पर सीएमओ ने नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण में सामने आई लापरवाही को गंभीरता से लेते श्री पाण्डेय ने संबंधित

कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों के एक दिवस के वेतन में कटौती किए जाने के आदेश जारी किए। निरीक्षण के दौरान सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने तथा अपने दायित्वों का पूर्ण निष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करने के निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कार्यालयीन व्यवस्था का सुचारु एवं अनुशासित होना आवश्यक है। श्री पाण्डेय ने स्पष्ट चेतावनी देते कहा कि आगे में भी इस प्रकार के औचक निरीक्षण लगातार किए जाएंगे। यदि किसी कर्मचारी द्वारा लापरवाही, अनियमितता या अनुशासनहीनता बरती जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार सख्त से सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी कर्मचारियों को कार्यालयीन अनुशासन का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह के आतिथ्य में वाटिका ग्रार्डन में कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक संपन्न

सोहागपुर। प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय सिंह 'राहुल भैया' के मुख्य आतिथ्य में वाटिका ग्रार्डन में संवाद एंव कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस बैठक में समस्त मंडलम सेक्टर पदाधिकारी,युवक कांग्रेस के पदाधिकारी, सेवादल के पदाधिकारी , किसान कांग्रेस,महिला कांग्रेस, एनएसयूआई एंव कांग्रेस के समस्त प्रकोष्ठो के पदाधिकारियों के नगर एवं आसपास के ग्रामीण माखननगर,पिपरिया बनखेड़ी आदि के कांग्रेसी नेता जुटे थे। इस अवसर पर अजय सिंह राहुल भैया ने कहा कि भाजपा जिस थीम से प्रदेश में शासन कर रही है। इससे आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि सभी एक जुट होकर कांग्रेस के लिए कार्य करते रहे। आपने आगे कहा आप सभी ने भी याद किया यह बहुत बड़ी बात है। आप सभी को एवं पूर्व नपाध्यक्ष अभिलाष सिंह चंदेल, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष सुधीर ठाकुर,नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल आदि की तारीफ की।

श्रद्धांजलि- इसी अवसर पर नगर व ग्रामीण कांग्रेसियों को श्रद्धांजलि दी गई। उक्त कार्यक्रम की राहुल भैया ने मुक्त कंठ से तारीफ करते हुए कहा कि मैने अभी तक 36 जिले दौरे किए। लेकिन यहां दिवंगतों को श्रद्धांजलि देना एक की अच्छी पहल है।

उपस्थिति – प्रभारी संजू शर्मा,महेंद्र सिंह चौहान, जिला कांग्रेस अध्यक्ष गुड्डन पांडे, कविंद्र रघुवंशी, पूर्व नपाध्यक्ष अध्यक्ष राजेंद्रसिंह चौधरी, राममूर्ति पटेल, वरिष्ठ नेता मेहरबान सिंह पटेल, पूर्व नपाध्यक्ष संतोष मालवीय, वरिष्ठ नेता रणवीर सिंह पटेल, वरिष्ठ नेता पुष्पराज सिंह पटेल, राजकुमार केलू उपाध्याय, अमृत बंधु डेरिया, राजा पलिया बनखेड़ी,यशवंत राजपूत, जिला जनपद पंचायत सदस्य एवं पत्रकार हाकम सिंह पटेल,श्री साई दमन पटेल, पूर्व ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष आलोक जायसवाल, गुड्डू चौधरी, पार्षद गण आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सुधीर ठाकुर एवं पत्रकार आशीष आचार्य आदि ने किया।

स्पॉन्सरशिप योजना बनी जीवन का संबल बच्चे के सपनों को मिल रही नई उड़ान

विदिशा ,निप्र। शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। ऐसी ही एक पहल स्पॉन्सरशिप योजना है, जिसने गंजबासौदा निवासी एक निराश्रित परिवार को कठिन परिस्थितियों में सहारा देकर बच्चे के भविष्य को संवारने का कार्य किया है। गंजबासौदा के तिरंगा चौक निवासी श्रीमती सीमा (परिवर्तित नाम) के जीवन में वर्ष 2023 में उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, जब 17 मई 2023 को उनके पति का अचानक हृदयाघात से निधन हो गया। पति के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। परिवार में केवल वह और उनका छोटा बेटा हैं। सीमित संसाधनों और कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण परिवार का भरण-पोषण, बच्चे की पढ़ाई तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया। विपरीत परिस्थितियों के बीच महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम

से उनके बच्चे को स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ प्राप्त हुआ। योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता ने परिवार को नई उम्मीद दी। इस सहायता राशि का उपयोग बच्चे की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में किया जा रहा है। श्रीमती सीमा बताती हैं कि उनका बेटा अभी छोटा है, जिसके कारण वह नियमित रूप से मजदूरी या अन्य कार्य करने नहीं जा पाती थीं। ऐसे समय में स्पॉन्सरशिप योजना उनके लिए एक मजबूत सहारा बनकर सामने आई। योजना से प्राप्त आर्थिक सहयोग ने न केवल उनकी आर्थिक चिंताओं को कम किया, बल्कि उन्हें अपने बेटे की पढ़ाई और बेहतर भविष्य के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का अवसर भी दिया। उन्होंने बताया कि अब वह अपने बेटे को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करा पा रही हैं और उसके भविष्य को लेकर पहले की तुलना में अधिक आश्वस्त हैं। योजना से मिली सहायता ने उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया है तथा कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। श्रीमती सीमा ने मध्यप्रदेश शासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्पॉन्सरशिप योजना जरूरतमंद बच्चों और उनके परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह योजना आर्थिक संकट से जूझ रहे परिवारों के बच्चों को शिक्षा और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाएं न केवल बच्चों के वर्तमान को सुरक्षित बनाती हैं, बल्कि उनके उज्ज्वल और आत्मनिर्भर भविष्य की मजबूत नींव भी रखती हैं।

ग्रेडिंग माह की शिकायतों के निराकरण हेतु विभागों ने तय किए साप्ताहिक लक्ष्य

कलेक्टर ने लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में दिए प्रभावी समाधान के निर्देश

विदिशा ,निप्र। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने सोमवार को आयोजित लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों में लंबित शिकायतों एवं आवेदनों की स्थिति का गहन परीक्षण किया। बैठक के दौरान विशेष रूप से ग्रेडिंग माह के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर जोर दिया गया। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि शासन की प्राथमिकता नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के निराकरण में गंभीरता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें तथा लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। बैठक में विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों ने अपने-

अपने विभागों में लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए उनके निराकरण के लिए साप्ताहिक लक्ष्य स्वयं निर्धारित किए। अधिकारियों ने आगामी सप्ताह में निर्धारित संख्या में शिकायतों का निराकरण करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की तथा लक्ष्य आधारित कार्ययोजना प्रस्तुत की। कलेक्टर ने कहा कि निर्धारित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी और जिन विभागों द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया जाएगा उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं लक्ष्य पूर्ति में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि शिकायतों के निराकरण में केवल औपचारिकता न बरती जाए, बल्कि आवेदकों की वास्तविक समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से समन्वय एवं सक्रियता के साथ कार्य करते हुए जिले की शिकायत निवारण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने का आह्वान किया।

डेयरी पशुपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों को वितरित किए गए प्रमाण पत्र

विदिशा ,निप्र। आरसेटी (ऋस्श्वञ्जढ्ढ) विदिशा में आयोजित डेयरी पशुपालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज सफलतापूर्वक समापन एवं एसेसमेंट संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल महिला एवं पुरुष प्रतिभागियों को डेयरी व्यवसाय से संबंधित विभिन्न तकनीकी एवं व्यावहारिक पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रशिक्षण के दौरान वरिष्ठ पशु चिकित्सा विशेषज्ञ एवं मास्टर ट्रेनर डॉ. ओम प्रकाश चौबे (सेवानिवृत्त वेटरनरी अधिकारी) ने प्रतिभागियों को उन्नत डेयरी प्रबंधन, पशुओं के स्वास्थ्य संरक्षण, संतुलित आहार व्यवस्था, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की तकनीकों, रोग नियंत्रण एवं पशुपालन को लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। कार्यक्रम के समापन अवसर पर आयोजित एसेसमेंट के माध्यम से प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के दौरान अर्जित ज्ञान एवं कौशल का मूल्यांकन किया गया। इस अवसर पर आरसेटी विदिशा के निदेशक एफ.सी. महली एवं संस्थान के संकाय सदस्यों ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र वितरित किए। निदेशक श्री महली ने

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि डेयरी पशुपालन ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने का प्रभावी माध्यम है। प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान एवं तकनीकों का उपयोग कर प्रतिभागी स्वरोजगार के नए अवसर विकसित कर सकते हैं तथा अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों के उज्ज्वल भविष्य एवं सफल स्वरोजगार की शुभकामनाओं के साथ किया गया। प्रशिक्षणार्थियों ने भी कार्यक्रम कोड्ड उपयोगी बताते हुए प्राप्त ज्ञान को व्यवहारिक रूप से अपनाने का संकल्प लिया।

कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में मार्गों पर से सक्रियता से हटाया जा रहा अतिक्रमण

नगरीय क्षेत्रों में की जा रही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही

नर्मदापुरम ,निप्र। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जिले के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने एवं यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने हेतु नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संबंधित ठेला संचालकों एवं प्रतिष्ठान संचालकों को समझाइश भी दी जा रही है कि वे निर्धारित स्थानों पर ही अपने व्यवसाय का संचालन करें। इसी क्रम में नर्मदापुरम नगर पालिका अमले द्वारा वीआईपी रोड स्थित बजरंग मंदिर के सामने अव्यवस्थित रूप से लगे सब्जी के ठेलों को हटाकर उन्हें

व्यवस्थित रूप से सब्जी मंडी शेड में पहुंचाया गया। कार्रवाई के दौरान ठेला संचालकों को यातायात व्यवस्था एवं आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित स्थानों पर व्यवसाय संचालित करने के निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त पुलिस लाइन से लेकर बीएसएनएल चौराहे तक सड़क किनारे अव्यवस्थित रूप से लगे ठेलों को भी नगर पालिका अमले द्वारा उचित स्थान पर स्थानांतरित किया गया। वहीं माखन नगर नगर पालिका के अमले द्वारा भी मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिले में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

बरेली में टीबी मुक्त भारत अभियान अन्तर्गत आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजित फूड बास्केट का भी किया गया वितरण

रायसेन प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत विकासखंड बरेली अन्तर्गत ÷100 दिवसीय आयुष्मान आरोग्य अभियान÷ के तहत ग्राम डिब्बी, मनकापुर एवं पिपरिया खाकी में आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वर्ग, विशेषकर उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के निवासियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना एवं टीबी (क्षय रोग) जैसी गंभीर बीमारी की समय पर पहचान करना रहा। एल.टी.फाउन्डेषन(दावत राईस)मंडीदीप के माध्यम से टीबी मरीजों को फूड बास्केट वितरण किया गया। शिविर में आए नागरिकों की टीबी स्क्रीनिंग हीमोग्लोबिन, रक्तचाप, रक्त शर्करा एवं बीएमआई सहित अन्य जरूरी स्वास्थ्य परीक्षण भी किए गए। जिले में 375 हाई रिस्क ग्रामों का चिन्हांकन किया गया है। जिसमें से 246 ग्रामों में षिविर लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

कलेक्टर के निर्देश अनुसार रात्रि चौपाल के दौरान प्राप्त हुई विद्युत संबंधी समस्याओं पर हुई त्वरित कार्रवाई

विद्युत लोड एवं वोल्टेज की जांच करने घर-घर पहुंचे विद्युत विभाग कर्मचारी

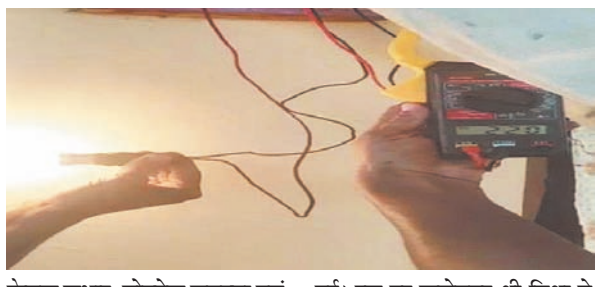

नर्मदापुरम ,निप्र। प्रशासन आपके द्वार÷ अभियान अंतर्गत आयोजित रात्रि चौपाल में विद्युत विभाग द्वारा ÷संपर्क अभियान÷ की जानकारी ग्रामवासियों को दी गई। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर विभिन्न विद्युत सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा प्राप्त शिकायतों का तत्काल निराकरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत मात्र 5 रुपए में नवीन ग्रामीण घरेलू एवं कृषि पंप कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। इसके साथ ही भार वृद्धि, नाम परिवर्तन, श्रेणी परिवर्तन, स्थाई कनेक्शन विच्छेदन, अस्थाई कनेक्शन, ई-केवाईसी, अनापत्ति प्रमाण पत्र, बंद अथवा खराब मीटर बदलना, स्मार्ट मीटर संबंधी शिकायतों का निराकरण, सर्विस

केबल सुधार, वोल्टेज समस्या एवं ट्रांसफार्मर से जुड़ी शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। साथ ही बिजली बिलों का आंशिक एवं पूर्ण भुगतान, अग्रिम भुगतान पर छूट, बकाया राशि भुगतान, समाधान योजना सहित अन्य जनहितैषी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ भी प्रदान किए जा रहे हैं। रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामवासियों द्वारा कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के समक्ष गांव में कम वोल्टेज एवं बिजली आपूर्ति बाधित होने की समस्या रखी गई। इस पर कलेक्टर श्री मिश्रा ने विद्युत विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश देते हुए गांव में घर-घर जाकर वोल्टेज लोड एवं विद्युत आपूर्ति की स्थिति की जांच करने तथा समस्याओं का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर के निर्देशों के परिपालन में विभागीय अमले द्वारा प्रत्येक प्राप्त शिकायत के अनुसार घर-घर जाकर वोल्टेज की जांच की गई तथा आवश्यक सुधार कार्य करते हुए विद्युत सप्लाई को सुचारु किया गया।

यूपीएससी व एमपीपीएससी परीक्षाओं में सफल पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि, आवेदन के लिए करें संपर्क

विदिशा ,निप्र। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संघ लोक सेवा आयोग (क्क्ष्ट) एवं राज्य लोक सेवा आयोग (स्क्क्ष्ट) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं में सफल हुए पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने की अपील की गई है। विभाग द्वारा जारी सूचना के अनुसार, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षाओं में चयनित पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार चरण में सफलता प्राप्त करने पर नियमानुसार प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। जिले के ऐसे सभी पात्र अभ्यर्थी, जिन्होंने क्क्ष्ट या स्क्क्ष्ट द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के किसी भी चरण–प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार–में सफलता प्राप्त की है, वे प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों सहित कार्यालय सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, कक्ष क्रमांक 117, भूतल, कम्पोजिट भवन, कलेक्टर कार्यालय, जिला विदिशा में संपर्क कर सकते हैं। विभाग ने पात्र अभ्यर्थियों से समय पर आवेदन प्रस्तुत कर योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है। यह योजना पिछड़ा वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उच्च प्रशासनिक सेवाओं की ओर प्रोत्साहित करने तथा उनके शैक्षणिक एवं प्रतियोगी परीक्षा प्रयासों को समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है।

संपर्क अभियान बना उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी माध्यम

विदिशा ,निप्र। विदिशा जिले में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित संपर्क अभियान उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं का त्वरित लाभ पहुंचाने और उनकी समस्याओं के प्रभावी समाधान का सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। 12 माह की इस विशेष पहल का उद्देश्य उपभोक्ता सहभागिता को मजबूत करना, बिलिंग एवं राजस्व संग्रहण की दक्षता बढ़ाना, तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी लाना तथा कंपनी की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करना है। अभियान के अंतर्गत आयोजित एकीकृत सेवा शिविरों में उपभोक्ताओं को बिल सुधार, भुगतान संग्रह, शिकायत निवारण, नवीन विद्युत कनेक्शन, मीटर एवं सर्विस केबल संबंधी सहायता सहित विभिन्न विद्युत सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही समाधान एवं कृषि वर्ष जैसी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। जिले में इस अभियान का शुभारंभ 14 मई 2026 को हुआ। 14 मई से 30 मई 2026 तक कुल 51 स्थानों पर शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें 4,452 शिकायतें एवं आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 4,073 मामलों का निराकरण कर दिया गया, जो कुल शिकायतों का लगभग 92 प्रतिशत है। 56 शिकायतें अपात्र पाई गईं, जबकि 323 मामले बिलिंग संबंधी होने के कारण प्रक्रियाधीन हैं, जिनका शीघ्र निराकरण किया जाएगा। शिविरों में सबसे अधिक 1,419 भुगतान संबंधी शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 99.22 प्रतिशत मामलों का समाधान किया गया। इसी प्रकार 1,083 नवीन विद्युत कनेक्शन संबंधी आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 93.35 प्रतिशत का निराकरण करते हुए उपभोक्ताओं को मौके पर ही कंपनी की 5 रुपये कनेक्शन योजना के अंतर्गत नवीन कनेक्शन प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति से संबंधित 168 शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया गया। अभियान के दौरान केवल शिकायतों का समाधान ही नहीं किया गया, बल्कि विद्युत वितरण व्यवस्था को भी मजबूत बनाया गया। बासौदा संभाग में एक वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता 25 केवीए से बढ़ाकर 63 केवीए की गई। इसके अलावा आठ स्थानों पर एलटी केबल बदली गई तथा एक ट्रांसफार्मर की फेसिंग कर विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार किया गया। अभियान की सफलता को देखते हुए कंपनी ने इसे पूरे वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया है। अब प्रत्येक वितरण केंद्र पर प्रतिमाह तीन शिविर अलग-अलग ग्रामों में आयोजित किए जाएंगे, जहां उपभोक्ताओं की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। यह अभियान न केवल उपभोक्ताओं को उनके गांव में ही बेहतर विद्युत सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, बल्कि विद्युत विभाग और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास एवं संवाद को भी मजबूत कर रहा है। संपर्क अभियान की यह सफलता ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जनसेवा के एक प्रभावी मॉडल के रूप में उभर रही है।

गौशालाओं में पशुओं की सुबह-शाम गणना होगी, लापरवाही पर पंजीयन निरस्तीकरण की कार्रवाई के निर्देश

विदिशा ,निप्र। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने जिले में संचालित पंजीकृत गौशालाओं के प्रभावी संचालन एवं पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने लंबित आवेदनों की समीक्षा बैठक के दौरान पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग एवं राजस्व अधिकारियों को गौशालाओं की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि जिले की सभी पंजीकृत गौशालाओं में रखे गए पशुओं की प्रतिदिन सुबह एवं शाम गणना कराई जाए, ताकि पशुओं की वास्तविक संख्या का सही रिकॉर्ड उपलब्ध रहे और किसी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके। उन्होंने

निर्देश दिए कि प्रत्येक गौशाला की मैपिंग भी कराई जाए तथा वहां उपलब्ध सुविधाओं और पशुओं की स्थिति का नियमित सत्यापन किया जाए। बैठक में कलेक्टर ने पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के उप संचालक डॉ. एन.के. शुक्ला को निर्देशित किया कि जिन गौशालाओं के संचालन में लापरवाही, अनियमितता अथवा निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाया जाए, उनके पंजीयन निरस्तीकरण का प्रस्ताव नियमानुसार तैयार कर संबंधित स्तर पर प्रेषित किया जाए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों (एसडीएम) को भी निर्देश दिए कि गौशालाओं में पशुओं की गणना और अभिलेखों का सत्यापन शिक्षित एवं जिम्मेदार अधिकारियों के माध्यम से कराया जाए, ताकि आंकड़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि गौवंश संरक्षण राज्य शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बैठक में गौशालाओं के संचालन, पशुओं के रख-रखाव एवं निगरानी व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

पीएम राहत योजना में घायलों को समय पर लाभ दिलाना सुनिश्चित करें - कलेक्टर डॉ सोनवणे

बैतूल ,निप्र। कलेक्टर डॉ सौरभ संजय सोनवणे ने पीएम राहत योजना के अंतर्गत प्रकरणों के समय पर रजिस्ट्रेशन होने के सम्बन्ध में निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने निजी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए पीएम राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुनः प्रशिक्षण आयोजित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने कहा कि पीएम राहत योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को त्वरित उपचार के लिए 1.5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने निर्देश दिए कि योजना का लाभ प्रत्येक पात्र प्रभावित व्यक्ति तक समय पर पहुंचे और कोई भी वंचित न रहे। बैठक में उन्होंने पुलिस विभाग को सड़क दुर्घटना में घायलों के त्वरित

रजिस्ट्रेशन एवं अस्पताल में भर्ती कराने में सहयोग करने वाले पुलिस कर्मियों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। साथ ही जिला अस्पताल में सड़क दुर्घटना के घायलों के लिए योजना अंतर्गत उपचार सुनिश्चित कराने के लिए एक डेडिकेटेड अधिकारी/कर्मचारी नियुक्त करने को कहा। योजना के प्रचार-प्रसार के लिए अस्पतालों में जानकारी संबंधी फ्लेक्स लगाने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर विशेष जोर देते हुए कहा कि योजना के सफल एवं सुचारू क्रियान्वयन के लिए निर्धारित एसओपी तैयार की जाए। उन्होंने दोनों विभागों में समन्वय स्थापित करने हेतु नोडलअधिकारियों की नियुक्ति कर उनकी सूची साझा करने के निर्देश भी दिए। ''पीएम राहत योजना'' से सड़क दुर्घटना पीड़ित का 01 लाख 50 हजार रूपये तक का कैशलेस उपचार होगा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम राहत (सड़क दुर्घटना पीड़ितों का कैशलेस उपचार) योजना 13 फरवरी-2026 से सम्पूर्ण भारत में लागू की गई है। योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति को डेढ़ लाख तक मुफ्त ईलाज सरकारी एवं चिन्हित प्रायवेट अस्पतालों में मिलेगा।

विधानसभा में मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बाबूलाल गौर की जंयती पर आयोजित कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव। इस अवसर पर राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर सहित कई नेता मौजूद थे। **फोटो: प्रवीण वाजपेयी।**

बाबूलाल जी गौर ने जनहितैषी कार्यों से लोगों के दिलों में बनाई जगह : सीएम

श्रद्धेय गौर जी सदैव हमारे लिए आशीर्वाददाता की भूमिका में रहे, मुख्यमंत्री ने पुष्पांजलि अर्पित की

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय बाबूलाल गौर की जयंती पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनके कार्यकाल के स्वर्णिम क्षणों का स्मरण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि श्रद्धेय बाबूलाल गौर जी मध्यप्रदेश के ऐसे राजनेता रहे, जिन्होंने अपने जनहितैषी कार्यों से लोगों के दिलों में जगह बनाई। वे सदैव हमारे लिए आशीर्वाददाता की भूमिका में रहे। राज्य सरकार उनके बताए मार्ग और आदर्शों का अनुसरण करते हुए प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

राजधानी भोपाल के वीआईपी रोड के विकास में गौर की दृढ़ता स्मरणीय

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि श्रद्धेय बाबूलाल जी ने अपने राजनीतिक जीवन में विभिन्न जनआंदोलनों में सक्रिय सहभागिता करते हुए राष्ट्रसेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका समर्पित सार्वजनिक जीवन और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता सभी के लिए प्रेरणास्रोत हैं। बाबूलाल जी गौर ने प्रदेश के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेशवासियों की सेवा की। प्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए उनका अमूल्य योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। राजधानी भोपाल के वीआईपी रोड के विकास में उनकी दृढ़ता स्मरणीय है।

मंत्री, जनप्रतिनिधि तथा परिजन ने भी अर्पित की पुष्पांजलि- मध्यप्रदेश विधानसभा में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी, नगरीय विकास एवं आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, विधायक श्री भगवानदास सबनानी, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा तथा परिजन सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

ट्विशा केस

पति और सास को जेल भेजा

सीबीआई ने नहीं मांगी रिमांड, गिरिबाला का आरोप- ट्विशा के वकील ने बेटे समर्थ से मारपीट की

भोपाल (नप्र)। सीबीआई की विशेष अदालत ने ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सीबीआई ने दोनों आरोपियों की पुलिस रिमांड नहीं मांगी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 16 जून तक भोपाल सेंट्रल जेल भेजने का आदेश दिया। दोनों को अन्य कैदियों से अलग रखा जाएगा। इससे पहले भोपाल के ट्विशा शर्मा डेथ केस में रिमांड खत्म होने के बाद मंगलवार को गिरिबाला और समर्थ को सीबीआई ने सीजेएम कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट रूम के अंदर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच बहस हुई।

सुनवाई के दौरान गिरिबाला ने आरोप लगाया कि ट्विशा के वकील अनुराग श्रीवास्तव ने जबलपुर कोर्ट में उनके बेटे समर्थ के साथ मारपीट की। इस पर अनुराग श्रीवास्तव ने जवाब देते हुए कहा कि जबलपुर कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो कोर्ट की फुटेज निकलवा कर जांच कर ली जाए।

अनुराग श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि समर्थ को बताना चाहिए कि वह जबलपुर कोर्ट में कहां छिपे थे। उन्होंने कहा कि कोर्ट भी इस सवाल का जवाब देगा।

ट्विशा शर्मा केस में गवाह नीरज दुबे पर जानलेवा हमला, पति समर्थ सिंह के दोस्तों पर लगा आरोप

राजधानी के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की कस्टडी और छानबीन के बीच एक बेहद गंभीर घटनाक्रम सामने आया है। इस हाई-प्रोफाइल केस के एक मुख्य गवाह नीरज दुबे पर सरेआम बीच बाजार में जानलेवा हमला किया गया है। पीड़ित का आरोप है कि मुख्य आरोपी पति समर्थ सिंह के दोस्तों ने उन्हें रास्ते में घेरकर बेरहमी से पीटा और इस मामले में गवाही देने पर गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी। इस घटना के बाद से केस से जुड़े अन्य गवाहों और पीड़ित परिवार में सुरक्षा को लेकर खौफ का माहौल है।पीड़ित नीरज दुबे भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में आरोपी समर्थ सिंह की मां और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह के घर के पास ही एक सांची पार्लर और सैलून चलाते हैं। नीरज के मुताबिक, वारदात 30 मई की है जब आरोपी समर्थ सिंह के दोस्त संदीप भट्टाचार्य ने अपने 4-5 साथियों के साथ मिलकर उन्हें घेर लिया। हमलावरों ने सीधे तौर पर सवाल किया कि तुम इस मामले में गवाह क्यों बन रहे हो? इसके बाद आरोपियों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इस पूरी मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ युवक नीरज को सरेआम बाजार में गालियां देते और मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

गर्भवती दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात की अनुमति नहीं

जबलपुर (नप्र)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दुष्कर्म से गर्भवती हुई 16 साल की नाबालिग को 31 सप्ताह के गर्भ का गर्भपात कराने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि गर्भ में पल रहे शिशु का विकास ऐसे स्तर पर पहुंच चुका है, जहां गर्भपात की अनुमति देना उसके जीवन को समाप्त करने के समान होगा। साथ ही चिकित्सकीय रिपोर्ट के अनुसार गर्भसमापन से किशोरी की जान को भी गंभीर खतरा हो सकता है। जस्टिस विवेक जैन की वेकेशन बेंच ने याचिका खारिज करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि पीड़िता के उपचार, प्रसव और बच्चे की देखभाल की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

बसों का किराया नहीं बढ़ा तो थम सकते हैं पहिए

ईंधन, महंगाई से परेशान बस मालिक आज परिवहन मंत्री से करेंगे बात, हड़ताल पर फैसला संभव

भोपाल (नप्र)। ईरान युद्ध के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी अब प्रदेश की बस परिवहन व्यवस्था पर सीधा असर डाल रही है। डीजल, टायर और अन्य ऑटो पार्ट्स महंगे होने से बस संचालन की लागत बेकाबू हो गई है। इसी संकट के बीच बस मालिकों ने सरकार के सामने किराया बढ़ाने की मांग को लेकर दबाव बढ़ा दिया है।

बस मालिकों के प्रतिनिधि आज शाम भोपाल में परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से इस मुद्दे पर अहम बातचीत करेंगे। इस बैठक को लेकर परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों में काफी उम्मीदें हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी भी साफ है, यदि सरकार ने मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो आज शाम ही बसों की हड़ताल का ऐलान किया जा सकता है। बस संचालकों ने बताया कि वे पिछले तीन वर्षों से किराया वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है। आखिरी बार 20 अप्रैल 2021 को किराया तय किया गया था, जिसमें अपेक्षित वृद्धि नहीं मिल सकी थी।

बसों की बढ़ती कीमत और रखरखाव में अधिक खर्च

संचालकों का कहना है कि महंगाई, कोरोना काल के नुकसान और नई नीतियों ने इस व्यवसाय को गंभीर संकट में डाल दिया है। यूरो-6 बसों की बढ़ती कीमत और रखरखाव खर्च ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। मई महीने में ही चार बार डीजल के दाम बढ़ने से संचालन लागत में लगातार इजाफा हुआ है, जबकि किराया वर्षों से स्थिर है। इससे आर्थिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। बस मालिकों ने सरकार से न्यूनतम किराया 2.50 रुपए प्रति किलोमीटर तय करने और अन्य श्रेणियों में भी उसी अनुपात में वृद्धि करने की मांग की है। उनका कहना है कि यात्री सुरक्षा से समझौता किए बिना इस व्यवसाय को चलाना तभी संभव है, जब समय-समय पर किराया संशोधन किया जाए।

सरकार ने किराया नहीं बढ़ाया तो हड़ताल करेंगे

मध्य प्रदेश बस ओनर एसोसिएशन के महामंत्री जयकुमार जैन ने स्पष्ट कहा कि लंबे समय से डीजल और बसों के पार्ट्स की कीमतों में कई बार भारी वृद्धि हुई है, लेकिन बस किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि घाटा सहने की सभी सीमाएं पार हो गई हैं और बिना किराया बढ़ाए इस व्यवसाय को चलाना संभव नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि शासन की उदासीनता के कारण न केवल व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा पर भी असर पड़ने की आशंका है। जैन ने कहा कि यदि सात दिन के भीतर किराया नहीं बढ़ाया गया तो बस मालिक किसी भी दिन बसों का संचालन बंद कर हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे, इसे हड़ताल समझा जाए या घाटे से उपजी मजबूरी।

हिल स्टेशन पचमढ़ी से भी ठंडा श्योपुर, पारा 9.6 डिग्री लुढ़का

रात का तापमान 15.4 डिग्री, नीमच में आंधी से छत गिरी, मां-बेटे की मौत

भोपाल (नप्र)। नौतपा में 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के आधे हिस्से में आंधी, बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई। बारिश के चलते दिन और रात के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई।

सबसे ज्यादा असर श्योपुर में देखने को मिला। यहां एक ही रात में तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया। न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री दर्ज किया गया। यह प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी से भी कम रहा।मौसम विभाग के अनुसार, सतना में करीब एक इंच, बैतूल में पौन इंच और श्योपुर में आधा इंच से अधिक बारिश हुई। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, गुना, दतिया, नर्मदापुरम, शिवपुरी, सीहोर, देवास, मंदसौर, धार, खंडवा और हरदा समेत कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का असर रहा। बारिश के कारण रात के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। भोपाल में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री, इंदौर में 22.1 डिग्री, उज्जैन में 21 डिग्री,

ग्वालियर में 25.4 डिग्री और जबलपुर में 26.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम में आई इस नरमी से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है।वहीं नीमच जिले के सिंगोली में सोमवार रात जर्जर मकान की छत ढहने से मां-बेटे की मौत हो गई। मृतकों की पहचान सोसर बाई धनोतिया और बेटे नीलेश धनोतिया के रूप में हुई है। नीलेश सिंगोली में अखबार बांटने का काम करता था।

40 किमी घंटे की रफ्तार से चल सकती है आंधी

मौसम विभाग की मानें तो कुछ घंटे के दौरान प्रदेश के 13 जिलों में मौसम बदल सकता है। सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, मैहर, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, उमरिया और कटनी में बिजली चमकने-गिरने के साथ आंधी चल सकती है। आंधी की रफ्तार 40 किमी प्रतिघंटा या इससे अधिक हो सकती है।

इस बार समय पर नहीं आएगा मानसून

मौसम विभाग के अनुसार, वर्तमान में प्री-मानसून की एक्टिविटी है। ट्रफ, वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) की वजह से बारिश का दौर चल रहा है। दूसरी ओर इस बार प्रदेश में मानसून की दस्तक 5 से 7 दिन लेट हो सकती है। बता दें कि प्रदेश में मानसून के एंटर की सामान्य तारीख 15 जून है। दक्षिणी हिस्से से मानसून एमपी में दस्तक देता है। साल 2025 में 1 दिन बाद यानी, 16 जून को मानसून एंटर हो गया था, जबकि विदाई 15 अक्टूबर तक हुई थी। इस साल मानसून अभी केरल में ही नहीं पहुंचा है। सामान्यतः केरल में आने के 15 दिन बाद एमपी में भी मानसून दस्तक दे देता है। कई बार ब्रेक भी हो जाता है। इस वजह से अबकी बार मानसून के प्रदेश में आने की तारीख 20 से 22 जून बताई जा रही है।

मां गिड़गिड़ाती रही पर ब्लड बैंक ने नहीं दिया एक यूनिट खून

दुर्ग जिला अस्पताल में हीमोग्लोबिन 5 ग्राम होने पर युवती ने तोड़ा दम

दुर्ग (नप्र)। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक 20 साल की युवती की मौत हो गई। स्वजनों के मुताबिक युवती के शरीर में खून की भारी कमी थी, इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन ने उसे एक यूनिट ब्लड तक नहीं दिया। समय पर खून न मिलने के कारण उसकी जान चली गई। युवती के स्वजन ब्लड बैंक भी गए थे। लेकिन वहां कार्यरत स्टाफ ने खून देने के लिए पर्ची और एक ब्लड डोनर लाने को कहा।

सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित थी युवती- अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक, युवती सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित थी और उसका इलाज चल रहा था। उसका ब्लड ग्रुप ओ-पॉजिटिव था और हीमोग्लोबिन घटकर करीब पांच ग्राम रह गया था। डॉक्टरों का यह भी मानना है कि अगर रिश्तेदारों के पास डोनर नहीं था, तो भी अस्पताल के स्टॉक से उसे कम से कम एक या दो यूनिट ब्लड दिया जा सकता था।

डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर में खून की मात्रा काफी कम है और तुरंत ब्लड चढ़ाने की जरूरत है। परिवार का आरोप है कि अस्पताल की ओर से तीन यूनिट ब्लड की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वे तुरंत डोनर नहीं जुटा सके। उन्होंने अस्पताल स्टाफ और ब्लड बैंक से कम से कम एक यूनिट ब्लड देने की मांग की, ताकि इलाज शुरू हो सके, लेकिन उन्हें खून नहीं दिया गया।

सोमवार शाम इलाज के दौरान दीपिका ने दम तोड़ दिया। रिश्तेदारों ने अस्पताल मैनेजमेंट पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दीपिका की मां ने बताया कि डॉक्टरों ने कहा था कि उसकी ब्लड रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन का लेवल करीब पांच ग्राम था।

डोनर न होने पर नहीं मिला खून

प्राप्त जानकारी के मुताबिक युवती का नाम दीपिका गाड़ा है, जो मरोदा भिलाई की रहने वाली थी। दीपिका कई दिनों से बीमार थी। उसके हाथ-पैर, कमर और पूरे शरीर में दर्द की शिकायत थी। तबीयत बिगड़ने पर शनिवार रात करीब 11 बजे उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया। जांच के बाद

सिविल सर्जन ने जताई एस्पिरेशन की आशंका

वहीं सिविल सर्जन डॉ. आशीषन मिंज ने बताया कि युवती सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित थी और उसका इलाज चल रहा था। उन्होंने बताया कि दीपिका का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था और उसका हीमोग्लोबिन स्तर करीब पांच ग्राम था। सीएस का कहना है कि मौत का कारण केवल खून की कमी होना जरूरी नहीं है। उन्होंने बताया कि आईसीयू के डॉक्टरों ने उन्हें आशंका जताई है कि युवती को एस्पिरेशन की समस्या भी हो सकती है। यानी खाना या कोई अन्य पदार्थ सांस की नली के रास्ते फेफड़ों में पहुंच गया हो, जिससे सांस लेने में गंभीर दिक्कत हुई हो। युवती की मौत सिकल सेल एनीमिया, एस्पिरेशन या किसी अन्य चिकित्सकीय कारण से भी हो सकती है। कारण का खुलासा पीएम के बाद हो पाएगा।

बेटे की छठी पर चली गोली से मां की मौत

पति और जेठ ने डीप फ्रीजर में छिपाई लाश

ग्वालियर (नप्र)। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। यहां एक घर में छह दिन पहले जन्मे बच्चे की 'छठी' की रस्में चल रही थीं। मेहमान जुटे हुए थे और चारों तरफ खुशियों का माहौल था। इसी बीच बंदूक की ट्रिगर पर दबी एक उंगली ने इन खुशियों को हमेशा के लिए मातम में बदल दिया। हर्ष फायरिंग की तैयारी के दौरान चली एक मिसफायर गोली सीधे बच्चे की मां को जा लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

अस्पताल ले जाने के बजाय शव को फ्रीजर में छुपाया- घटना रविवार सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच की है। पुलिस के मुताबिक, मनोज कुशवाह के घर पर कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थीं। इसी दौरान मनोज का भाई योगेश एक अवैध कट्टे में बार-बार गोली लोड और अनलोड कर रहा था। इसी कशमकश में अचानक कट्टे से फायर हो गया और गोली सीधे नवजात की मां जाह्नवी उर्फ ज्योति (32 वर्ष) के सिर में जा धंसी। जाह्नवी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद जो हुआ, उसने सबको चौंका दिया। पति मनोज और जेठ योगेश ने पुलिस या अस्पताल भागने के बजाय मौत को छुपाने की साजिश रची। वे एक बड़ा डीप फ्रीजर लेकर आए और जाह्नवी की लाश को उसमें बंद कर दिया ताकि बिना किसी को भनक लगे उसका अंतिम संस्कार किया जा सके।

लहूलुहान बेटे को लेकर दंडवत करती जनसुनवाई में पहुंची मां, गांव के दबंगों पर मारपीट करने का आरोप; बोली- इतना मारा कि सिर में 20 टांके आए

गुना (नप्र)। बमोरी थाना क्षेत्र के ग्राम रामपुर से दबंगों के आतंक और पुलिस की कथित अनदेखी से त्रस्त होकर एक मां अपने लहूलुहान बेटे को लेकर नंगे पैर दंडवत प्रणाम करते हुए न्याय की गुहार लगाने कलेक्ट्रेट पहुंची। झुलसा देने वाली धूप और तपती सड़क की परवाह किए बिना जब यह बेबस परिवार रेंगते हुए जनसुनवाई में पहुंचा, तो वहां मौजूद प्रशासन हरकत में आ गया। इस दौरान तहसीलदार ने मां-बेटे को उठाकर अपने साथ ऊपर ले गए। बाद में कलेक्ट्रेट से पीड़ित परिवार को एसपी कार्यालय भेजा गया।

पुश्तैनी मकान पर कब्जे की नीयत का आरोप- जानकारी के अनुसार, पीड़ित जितेंद्र रजक पुत्र हल्के रजक और उसकी वृद्ध मां रतनबाई ने जिला प्रशासन के सामने रो-रोकर अपनी आपबीती सुनाई। पीड़ितों ने बताया कि गांव के ही रसूखदार मलखान यादव, मांगीलाल यादव, प्रताप यादव और विक्रम यादव पिछले लंबे समय से उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं।

दबंगों की नजर उनके पुश्तैनी मकान पर है, जिसे वे जबरन औने-पौने दामों में खरीदना चाहते हैं। जब परिवार ने अपना घर बेचने से साफ इनकार कर दिया, तो आरोपियों ने उनका जीना मुहाल कर दिया और आए दिन पूरे परिवार को गांव छोड़ने या जान से मारने की धमकियां देने लगे।

घर में घुसकर मारपीट की- कलेक्टर को दिए शिकायती आवेदन में जितेंद्र रजक ने बताया कि घटना बीते शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे की है। वह अपने घर पर था, तभी चारों आरोपी लाठी-डंडे लेकर उसके घर में घुस आए और गाली-गलौज करते हुए जमकर मारपीट की। इसमें जितेंद्र का सिर फट गया, जिस पर 20 टांके आए हैं। इसके अलावा उसके हाथ-पैर और जांघों पर भी गंभीर चोटों के निशान हैं।

पीड़ित ने एफआईआर को बताया झूठा- रिकॉर्ड के अनुसार, बमोरी थाने में आरोपी पक्ष के विक्रम सिंह यादव की शिकायत पर जितेंद्र रजक के खिलाफ धारा 122/2026 के तहत शराब पीकर गाली-गलौज करने और मांगीलाल यादव के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। जितेंद्र का कहना है कि यह एफआईआर पूरी तरह झूठी है और उसे व उसके परिवार को फंसाने के लिए पुलिस की मदद से तैयार की गई है।

खौफ के साए में जीने को मजबूर परिवार- कलेक्ट्रेट पहुंचे पीड़ितों ने बताया कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी नामजद आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस दंडात्मक कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे उनके हौसले और अधिक बढ़ गए हैं। आरोपी अब हथियार लहराते हुए पीड़ित के घर के चक्कर काट रहे हैं और शिकायत वापस न लेने पर पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं।

इस खौफ के कारण जितेंद्र और उसका परिवार मजदूरी पर भी नहीं जा पा रहा है। पूरा परिवार घर के भीतर कैद होकर भय के साए में जीने को मजबूर है।

दोनों पक्षों की जांच कर रही पुलिस- इस मामले में एसडीओपी विवेक अष्ठाना ने बताया कि जितेंद्र पर बमोरी थाने में 65 वर्षीय बुजुर्ग मांगीलाल यादव के साथ मारपीट करने का आरोप है। उन्होंने कहा कि उक्त युवक शराब के नशे में आए दिन उत्पात करता है। यह जानकारी सरपंच सहित गांव के अधिकांश लोगों ने दी है। एसडीओपी के अनुसार, गत दिवस भी पति-पत्नी के बीच विवाद हो रहा था। इसी दौरान जितेंद्र ने पड़ोसी मांगीलाल के साथ भी मारपीट कर दी। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई की जा रही है। जितेंद्र ने भी अपने साथ मारपीट होने की बात कही है। उसका मेडिकल और एक्स-रे कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।